RNI .NO. MPBIL / 2013/ 54381

संपादकः- डॉ. देवेन्द्र मालवीय

11 वर्ष

दैनिक
सद्भावना पाती

...प्राणियों में सद्भावना हो...

www.sadbhawnapaati.com Email: sadbhawnapaatinews@gmail.com इंदौर शुक्रवार ●15 दिसंबर , 2023 वर्षः-11 अंक - 227 मूल्य -1 रु. कुल पृष्ठ - 8

"उन्नत भारत अभियान" part 2

इंदौर में "शिक्षा सेवा नहीं लाभ का धंधा"

200 से अधिक इंस्टिट्यूट, 11 प्राइवेट युनिवर्सिटी,UBA से जुड़े मात्र 18, आईपीएस एकेडमी अव्वल

पूनम शर्मा

इंदौर। मध्य भारत में एजुकेशन हब के रूप में विकसित हो चुके इंदौर में 200 से अधिक इंस्टीट्यूट/ कॉलेज, 11 प्राइवेट यूनिवर्सिटी के साथ अनेक शैक्षणिक संस्थान कार्यरत हैं लेकिन यहाँ शिक्षा सेवा नहीं बल्कि लाभ का धंधा मात्र है। प्राइवेट यूनिवर्सिटियां भारी भरकम फीस लेकर सिर्फ डिग्री बांटने का काम कर रही हैं। सामाजिक सरोकार से इनका कोई वास्ता नहीं है। देश में प्रतिष्ठित देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में 30 से अधिक विभाग हैं जो यदि एक गाँव भी गोद लेते तो 30 से ज़्यादा गाँवों का विकास होता इसी प्रकार जिले में 200 से अधिक शैक्षणिक संसथान हैं। आदेशानुसार 5 गॉवों को गोद लेते तो इन गावों की संख्या 1000 से ऊपर होती। दुर्भाग्य है कि यहाँ कार्यान्वयन के लिए न तो जिला प्रशासन, न उच्च शिक्षा विभाग और न ही रीजनल कॉर्डिनेटिंग इंस्टिट्यूट इस योजना को गंभीरता से लागू करवा पा रहे हैं। शिक्षा क्षेत्र में सेवाभाव की कमी से इंदौर में सिर्फ 18 संस्थानों ने ही योजना में भागीदारी की है। जब इन गांवों में दैनिक सद्भावना पाती की टीम पहुंची तो पाया कि योजना के मूल उद्देश्यों का क्रियान्वयन नाम मात्र का है।

उन्नत भारत अभियान
UNNAT BHARAT ABHIYAN
शिक्षित भारत-स्वस्थ भारत- स्वच्छ भारत- स्वावलंबी भारत- संपन्न भारत

इंदौर की ये संस्थाएं है उन्नत भारत अभियान में "पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट"

- डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम युनिवर्सिटी
- एसडी बंसल कॉलेज ऑफ़ टेक्नोलॉजी
- प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ़ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट एंड रिसर्च
- एक्रोपॉलिस इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च
- बीएम कॉलेज ऑफ़ टेक्नोलॉजी
- चमेलीदेवी ग्रुप ऑफ़ इंस्टीट्यूशन्स
- चमेलीदेवी इंस्टीट्यूट ऑफ़ फार्मेसी
- देवी अहिल्या कॉलेज ऑफ़ फार्मेसी
- मॉडर्न इंस्टिट्यूट ऑफ़ प्रोफेशनल साइंस
- श्री वैष्णव इंस्टीट्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट
- आईपीएस एकेडमी
- जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट
- इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी (आईआईटी)
- पीडीपीएम - इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी
- महाराजा रंजीत सिंह कॉलेज ऑफ़ प्रोफेशनल साइंसेस
- मेडीकैप्स युनिवर्सिटी
- प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट एंडरिसर्च
- एसडी बंसल कॉलेज ऑफ़ इंजीनियरिंग

उक्त संस्थानों के अलावा कितने इंस्टिट्यूट योजना से जुड़े हैं और क्या प्रगति की है इसके लिए आईआईटी दिल्ली से इस सन्दर्भ में जानकारी मांगी गई थी लेकिन पूरी जानकारी नहीं दी गई, आगे पड़ताल के लिए दैनिक सद्भावना पाती अख़बार ने इंदौर की लगभग सारी शैक्षणिक संस्थाओं को ईमेल भेज जवाब चाहा तो रिप्लाई नगण्य रहा। हालाँकि कुछ संस्थाओं ने जवाब दिए जिनमें **आईपीएस एकेडमी ने किये गए कार्यों का मय दस्तावेज जवाब दिया। बता दें कि आईपीएस एकेडमी देश में स्थापित नाम है और सामाजिक सरोकार में शिद्दत से कार्य करता है।**

अभियान में संस्थानों की भागीदारी इसलिए भी बहुत कम है क्यूंकि प्रचार-प्रसार की कमी के साथ साथ जिन्हें ज़िम्मेदारी सौंपी जाती है वो अपना कार्य जवाबदारी से नहीं करते। रीजनल नोडल सेंटर (SGSITS, INDORE) तक को अपने अंतर्गत कार्य कर रहे संस्थानों के बारे में जानकारी नहीं है और महादुर्भाग्य की बात है नेशनल कॉर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट आईआईटी दिल्ली जो लम्बे समय से गाँवों के विकास के लिए कार्य कर रहा है वह स्वयं भी संस्थानों को भागीदारी करवाने के लिए गंभीर नहीं है।

उन्नत भारत अभियान तो इतना उन्नत है कि इसकी वेबसाइट जिसमें हज़ारों संस्थान की भागीदारी है, कई बार तो खुलती नहीं और खुलती है तो बफरिंग होती रहती है। मानव संसाधन मंत्रालय को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है।

संस्थानों को 50 हज़ार से एक लाख की होती है फंडिंग

अभियान की गाइडलाइन्स के अनुसार प्रत्येक पार्टिसिपेटिंग इंस्टिट्यूट को सीड मनी, पेरेनियल असिस्टेंस, एप्रीसिएशन फंडिंग टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट/कस्टमाइजेशन के रूप में 50 हज़ार से लेकर एक लाख तक की फंडिंग की जाती है इसका इस्तेमाल गाँवों में सर्वेक्षण, यात्रा, जलपान, जागरूकता कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं के लिए किया जा सकता है लेकिन ध्यान देने योग्य है कि इसके लिए कोई बिल लगाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक सामान्य सा व्यय विवरण (स्टेटमेंट ऑफ़ एक्सपेंडिचर) देना होता है और 2 हफ़्तों में फंड रिलीज़ कर दिया जाता है।

शहर में ये बड़ी संस्थाएं हैं जो इस योजना में भागीदारी कर सकती हैं बशर्ते कि इन्हें शिक्षा लाभ का धंधा नहीं बल्कि सेवा है यह मानना होगा, वहीं रीजनल नोडल सेंटर एवं नेशनल कॉर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट को इन संस्थानों से संपर्क करने की जरुरत है।

- अरिहंत कॉलेज एंड ग्रुप्स
- श्री अरविंदो मेडिकल कॉलेज एंड ग्रुप्स
- सेज युनिवर्सिटी
- ओरिएंटल युनिवर्सिटी
- चोइथराम इंस्टिट्यूट एंड ग्रुप्स
- गुजराती समाज स्कूल, कॉलेज एंड ग्रुप्स
- इस्लामिया करीमिया कॉलेज
- इंदौर लॉ कॉलेज एंड ग्रुप्स
- कान्यकुब्ज कॉलेज ग्रुप्स
- रेनेसा युनिवर्सिटी
- एलएनसीटी कॉलेज एंड ग्रुप्स
- एमबी खालसा कॉलेज एंड ग्रुप्स
- मालवा इंस्टिट्यूट एंड ग्रुप्स
- मथुरादेवी इंस्टिट्यूट एंड ग्रुप्स
- मातुश्री अहिल्या देवी कॉलेज एंड ग्रुप्स
- न्यू एरा बीएड, नर्सिंग कॉलेज एंड ग्रुप्स
- पायोनियर कॉलेज एंड ग्रुप्स
- संघवी इंस्टिट्यूट एंड ग्रुप्स
- श्री क्लॉथ मार्केट गर्ल्स कॉलेज एंड ग्रुप्स
- शुभदीप आयुर्वेदिक कॉलेज एंड ग्रुप्स
- विद्यासागर कॉलेज एंड ग्रुप्स
- विक्रांत ग्रुप्स ऑफ़ इंस्टीट्यूशन

भाजपा नेता की हथेली काटने वालों के घर बुलडोजर चला

● भोपाल में 5 आरोपियों के 3 मकान ढहाए, नए सीएम का पहला एक्शन

भोपाल (एजेंसी)। भोपाल में भाजपा नेता की हथेली काटने वाले 5 आरोपियों के 3 घर गुरुवार को बुलडोजर चलाकर ढहा दिए गए। आरोपियों ने 5 दिसंबर को तलवार मारकर जपा झुग्गी-झोपड़ी प्रकोष्ठ अरेरा मंडल के महामंत्री देवेंद्र सिंह ठाकुर की हथेली काट दी थी। हमले के 9वें दिन आरोपियों पर कार्रवाई हुई। डॉ. मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पहला एक्शन है।

5 दिसंबर को जनता कॉलोनी में रहने वाले आरोपी फारुख राइन उर्फ मिन्नी, असलम, समीर उर्फ बिल्लू, शाहरुख और बिलाल ने साईं बोर्ड के पास देवेंद्र सिंह पर हमला किया था। कोलार एसडीएम आशुतोष गोस्वामी के नेतृत्व में पहुंची नगर निगम की टीम ने इन आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाया। निगम के 25 से अधिक कर्मचारियों ने मकान तोड़ने की कार्रवाई की। किसी भी विवाद से निपटने के लिए पुलिस बल भी तैनात था।

अतिक्रमण अधिकारी प्रतीक गर्ग और हबीबगंज थाना प्रभारी मनीष राज सिंह भदौरिया ने बताया कि मकानों के अवैध हिस्से और अतिक्रमण को गिराया गया है। निगम के 25 से अधिक कर्मचारियों ने मकान तोड़ने की कार्रवाई की है। डेढ़ घंटे में अतिक्रमण को हटाया गया। बिल्डिंग परमिशन समेत अन्य अनुमतियां नहीं थी।

सभी आरोपी गिरफ्तार, एनएसए लगाया

देवेंद्र सिंह ठाकुर पर हमले के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 8 दिसंबर को भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह ने इनमें से एक आरोपी फारुख राइन उर्फ बिन्नी पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) लगाया था। आरोपी फारुख पर मारपीट के 14 केस दर्ज हैं। वह हबीबगंज पुलिस थाने की गुंडा लिस्ट में शामिल है। हमला करने वाले पांचों आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति के हैं।

खेत में फसल के बीच मिला प्रेमी जोड़े का शव, इलाके में फैली सनसनी, पुलिस जांच में जुटी

भोपाल/उमरिया (एजेंसी)। म.प्र. के उमरिया जिले के नौरोजाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत कंचन खुली खदान के बगल से अरहर के खेत में अज्ञात दो शव मिले है। इनके

मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मामले का पता तब चला जब ग्राम नौसेमर निवासी कमला पाल अपने खेत गया। कमला पाल ने बताया कि हम आज 15 दिन बाद आये तो अपने खेत मे बोई हुई अरहर की फसल घूम कर देखने लगे। इसी दौरान किसी मरे हुए जानवर जैसी दुर्गन्ध आई। पास जाकर देखा तो 2 शव पड़े हुए थे जिसमे 1 पुरुष और 1 महिला का शव था। दरअसल, गांव में मवेशियों से फसल को किसी तरह नुकसान नहीं होता है तो किसान 15-15 दिन बाद आकर फसल देखते हैं। इसके चलते घटना का पता नहीं चला। शव देखने वाले लोगों ने बताया कि महिला के शरीर पर कोई कपड़े नही थे। इसके अलावा उसको कुछ दूर घसीटा गया था। शव को देखते ही हमने सरपंच को बताया और पुलिस को सूचना दी।

मृतक युवक की हुई पहचान

खेत में मिले मृतक युवक की पहचान हो गई है। ग्राम लहंगी निवासी मृतक के भाई धनी राम बैगा ने बताया कि ये मेरा भाई शिव प्रसाद उर्फ मारू बैगा पिता मंगल बैगा है। इसकी उम्र लगभग 28 वर्ष है। ये पिछले बुधवार से लापता है। हम कल थाने में रिपोर्ट लिखवाने गए थे तो हमको कह दिए कि जाकर पता लगाओ फिर आना। हम वापस आकर पिताजी को नर्मदा भेजे थे तो वहां पता नहीं चला। आज वापस आये हैं तो उसके दो घण्टे बाद हमको पता चला कि यहां पर लाश है। आकर देखा की ये मेरे भाई की है।

सुरक्षा चूक मामले में विपक्षी सांसदों ने किया जमकर हंगामा

● लोकसभा से 14 सांसद, जबकि राज्यसभा का एक सांसद पूरे सत्र से सस्पेंड ● राज्यसभा से निलंबन के बावजूद सदन पहुंचे डेरेक ओ-ब्रायन

नई दिल्ली (एजेंसी)। संसद के शीतकालीन सत्र के नौवें दिन गुरुवार की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने संसद सुरक्षा चूक के मामले में जमकर हंगामा किया। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में विपक्षी नेताओं ने नारेबाजी की। दिन में कई बार सदन को स्थगित करना पड़ा।

कौन-कौन सांसद हुए निलंबित?

बता दें कि निलंबित किए गए विपक्षी सांसदों में बेनी बेहानन, वीके श्रीकंदन, मोहम्मद जावेद, पीआर नटराजन, कनिमोझी करुणानिधि, के सुब्रमण्यम, एसआर पार्थिबन, एस वेंकटेशन, मनिकम टैगोर, टीएन प्रतापन, हिबी ईडन, एस जोथिमणि, राम्या हरिदास और डीन कुरियाकोस शामिल हैं।

सस्पेंडेड सांसदों में सीपीआई (एम) और डीएमके के 2-2 और सीपीआई के एक नेता शामिल हैं। वहीं राज्यसभा से टीएमसी सांसद डेरेक ओ-ब्रायन को भी बचे हुए सत्र से निलंबित किया गया। दरअसल, डेरेक नारेबाजी करते हुए वेल में आ गए थे, जिससे स्पीकर जगदीप धनखड़ नाराज हो गए।

लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही सांसद नारेबाजी करने लगे

गुरुवार को सदन की कार्यवाही 11 बजे शुरू हुई। जैसे ही स्पीकर ओम बिड़ला लोकसभा पहुंचे तो विपक्षी सांसदों ने संसद की सुरक्षा को लेकर हंगामा करना शुरू कर दिया। उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह के इस्तीफ की मांग की। ओम बिड़ला ने सभी को शांति बनाए रखने को कहा। उन्होंने कहा कि कल हुई घटना से सभी चिंतित हैं, ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी और इस पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने सभी को विश्वास दिलाया कि लोकसभा अध्यक्ष होने के नाते सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी है।

भविष्य में सुरक्षा की सारी सावधानी बरती जाएगी : राजनाथ सिंह – लोकसभा में विपक्षी हंगामे के बीच राजनाथ सिंह ने कहा कि भविष्य में सुरक्षा की सारी सावधानी बरती जाएगी। वहीं, स्पीकर ओम बिड़ला ने मामले की जांच का आश्वासन दिया।

आदिवासियों की दशकों पुरानी समस्या होगी खत्म:सतपुड़ा पहाड़ों के बीच बसे नांदिया-चूरनी के लिए देनवा नदी पर बनेगा रपटा

कलेक्टर ने ग्रामीणों से किए वादे को पूरा करने के लिए शुरू की प्रक्रिया

नर्मदापुरम(निप्र)। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के बफर जोन में पहाड़ों के बीच बसे नांदिया, चूरनी गांव के लिए खुश खबर है। दशकों से देनवा नदी पर रपटा बनने का ग्रामीणों का इंतजार अब खत्म होगा। इन ग्रामीणों के आवागमन के लिए जल्द ही देनवा नदी पर करीब 1.80करोड़ रुपए की राशि से दो रपटे(पुलिया) का निर्माण होगा। रपटा बनने से बारिश, ठंड, गर्मी किसी भी सीजन में ये ग्रामीण आ-जा सकेंगे। बारिश में नदी का ज्यादा पानी भी ग्रामीणों की राह में बाधा नहीं डाल पाएगा। बता दें नर्मदापुरम जिले की सबसे आखिरी ग्राम पंचायत नांदिया है। जो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र में आती है। जो जिला मुख्यालय से करीब 180 किमी और ब्लॉक मुख्यालय से पिपरिया से 110 किमी है। पंचायत में चूरनी, नांदिया, सुख डोंगर समेत 6 गांव आते है। यहां पहुंचने के लिए छिंदवाड़ा जिले के देहखाली, भूराभगत होकर ही गांव आना-पड़ता है। रास्ते में देनवा नदी है। जिसे कई सालों से ग्रामीण पैदल ही पार करते आ रहे है। पंचायत में सभी आदिवासी वोटर है। सालों से पुल, रपटा बनाने की अपनी जायज मांग पूरी नहीं होने से ग्रामीणों ने चुनाव में बहिष्कार का फैसला किया था। दैनिक भास्कर डिजिटल ने सबसे पहले 14 नवंबर को ÷छह किमी पहाड़ चढ़कर वोट डालने जाते हैं लोग- पिछली बार 87व वोटिंग हुई थी; इस बार मतदान के बहिष्कार का फैसला इस शीर्षक से खबर को पब्लिश किया। खबर पब्लिश होते ही नर्मदापुरम ही नहीं, राज्य निर्वाचन आयोग तक में खलबली मच गई। एकाएक जिले से 180 दूर स्थित सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में बसे नांदिया में नर्मदापुरम कलेक्टर नीरज कुमार सिंह, एसपी डॉक्टर गुरकरन सिंह, जिला पंचायत सीईओ एसएस रावत, पिपरिया एसडीएम संतोष तिवारी तमाम अमले के साथ 14 नवंबर देर शाम जा पहुंचे थे। कलेक्टर, एसपी व सीईओ ने ग्राम चौपाल लगाकर ग्रामीणों से बातचीत की थी। उनकी समस्याओं को सुन, चुनाव के बाद रपटा बनवाने का वादा किया था। जिसके बाद ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार का फैसला बदला। 17 नवंबर को चूरनी और नांदिया दोनों ही मतदान केंद्रों पर 90 फीसदी मतदान हुआ। जिला प्रशासन ने वादा पूरा करते हुए 5 दिसंबर को रपटा बनवाने के लिए ग्रामीण यांत्रिक सेवा के कार्यपालन यंत्री ने टीएस जारी कर दी है। राशि स्वीकृति के लिए फाइल कलेक्टर के माध्यम से सरकार को भेजी जाएगी। यह स्वीकृति मिलने के बाद टेंडर जारी कर रपटे का निर्माण शुरू हो जाएगा।

केंद्रीय चुनाव आयुक्त कर चुके प्रशंसा

जिले के दुर्गम व पहाड़ों के बीच बसे नांदिया, चूरना केंद्र की केंद्रीय मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार प्रशंसा कर चुके है। चुनाव की घोषणा के साथ ही उन्होंने कहा था कि नर्मदापुरम जिले के जिले के इस दुर्गम मतदान केंद्र नांदिया। निर्वाचन टीम कठिन रास्तों से पार करते हुए पहुंचती और सफल मतदान कराती है। यहां के मतदाता जागरुक है। केंद्र को लोकतंत्र का आदर्श बताया था। लेकिन चुनाव से पहले रपटे की समस्या बरकरार रहने से ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार का फैसला लिया था।

खबर मिलने पर कलेक्टर नीरज कुमार सिंह, एसपी डॉक्टर गुरकरन सिंह, जिला सीईओ एसएस रावत, एसडीएम संतोष तिवारी ने जाकर ग्रामीणों को मनाया। ग्रामीणों ने खुलकर मतदान किया। 90 फीसदी मतदान हुआ। जिला प्रशासन ने ग्रामीणों की जायज मांग को पूरा करने के लिए रपटा बनवाने की प्रक्रिया शुरू की।

नर्मदापुरम में बीएमओ पर पेन से हमला-समीक्षा बैठक में काम करने का कहा तो कर्मचारी ने की मारपीट

नर्मदापुरम(निप्र)। नर्मदापुरम के माखननगर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बीएमओ डॉक्टर घनश्याम चौहान से मारपीट की गई। विभाग के कर्मचारी ने समीक्षा बैठक में कर्मचारियों के सामने बीएमओ चौहान पर पेन से हमला किया और झुमाझटकी की। उन्हें अपशब्द भी कहें। विवाद के बाद बीएमओ डॉक्टर चौहान ने माखननगर थाने में कर्मचारी के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा, मारपीट, गाली गलौच की धाराओं में केस दर्ज कराया।

पुलिस के मुताबिक डॉक्टर घनश्याम चौहान माखननगर में बीएमओ है। आरोपी हरगोविंद मीणा बागरातवा में एमपीडब्ल्यू है। बीएमओ ने बताया आज डीएचएच की बैठक नर्मदापुरम में होनी है। इसलिए मंगलवार को सभी राष्ट्रीय कार्यक्रमों की ब्लॉक स्तर पर समीक्षा बैठक रखी गई थी। जिसमें ब्लॉक के बीईई, बीसीएम, बीपीएम, सेक्टर सुपरवाइजर व अन्य कर्मचारी मौजूद थे। एमपीडब्ल्यू हरगोविंद मीणा से कहा कि अनमोल पोर्टल व एचएमआईएस पोर्टल पर रिपोर्ट लेकर ऑपरेटर से इंट्री करवा दीजिए। इसी बात पर एमपीडब्ल्यू मीणा बीएमओ पर आगबबूला हो गए। बैठक में सभी के सामने उन्होंने गालियां दी। बीएमओ ने अपशब्द का उपयोग न करने का कहा तो उसने अपने हाथ में रखे पेन से बीएमओ पर हमला कर दिया। बचाव में बीएमओ ने हाथ आगे किया। पेन उनके हाथ की हथेली में लग गया। जिससे खून बहने लगा। थाना प्रभारी राजपाल सिंह जादौन ने बताया बीएमओ से झगड़ा करने वाले कर्मचारी पर शासकीय कार्य में बाधा का केस दर्ज किया है।

संक्षिप्त समाचार

जनसुनवाई में नागरिकों की समस्याओं का हुआ निराकरण

रायसेन (निप्र)। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जनसुनवाई में कलेक्टर श्री अरविंद दुबे द्वारा नागरिकों की समस्याओं, शिकायतों पर सुनवाई करते हुए उनका निराकरण किया गया। उन्होंने कुछ प्रकरणों में संबंधित अधिकारियों को शीघ्र आवश्यक कार्यवाही कर निराकरण के निर्देश दिए। जनसुनवाई में अपर कलेक्टर श्री अभिषेक दुबे सहित अनेक विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

एड्स पखवाड़ा के अंतर्गत श्रमिकों जागरूकता शिविर आयोजित

सीहोर (निप्र)। एड्स पखवाड़ा-2023 के अंतर्गत चावडी में श्रमिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें बडी संख्या में उपस्थित श्रमिकों को एड्स से बचाव पर जागरूक किया गया। जिला एड्स नियंत्रण अधिकारी डॉ.जेडी कोरी ने बताया कि कांउसलर श्रीमती पुष्पा साहू तथा श्रीमती कामीनी गौर के द्वारा विस्तार से जानकारी दी गई। जिसमें बताया गया कि एड्स नामक इस भयानक बीमारी ने देश की एक बड़ी आबादी को अपने प्रभाव में जकड़ कर रखा है। देश में 15 से 49 वर्ष की आयु के बीच के लगभग 25 लाख लोग एड्स से प्रभवित है। यह आंकड़ा विश्व में एड्स प्रभावित लोगों की सूची में तीसरे स्थान पर आता है। एड्स एक ऐसी जानलेवा बीमारी है जो मानवीय प्रतिरक्षी अपूर्णता विषाणु एचआईवी संक्रमण के पश्चात मानवीय शरीर की प्रतिरोधक क्षमता घटने लगती है। उन्होंने बताया कि एड्स की पुष्टि चिकित्सकों द्वारा जांच के उपरांत ही की जा सकती है।

अंतराष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन पखवाड़े के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

नर्मदापुरम (निप्र)। नर्मदापुरम के पर्यटन स्थल मढ़ई में महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन स्थल परियोजना कार्यक्रम को जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में जिला पुरातत्व पर्यटन एवं संस्कृति परिषद एवं इंडियन ग्रामीण द्वारा महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन स्थल परियोजना कार्यक्रम अंतर्गत महिला हिंसा विरोध दिवस पखवाड़ा अन्तर्गत जागरुकता कार्यक्रम किया गया। जिसमें महिलाओ की सुरक्षा और उनके प्रति सम्मान का संदेश दिया गया और संदेशात्मक रैली निकाली गई। इस कार्यक्रम में जिला पुरातत्व पर्यटन एवं संस्कृति परिषद से पर्यटन प्रबंधक मनोज सिंह ठाकुर, इंडियन ग्रामीण सर्विसेज से अर्चना दास एवं प्रशिक्षक ओर सभी प्रशिक्षणार्थी मौजूद रहे।

जनसुनवाई में आए आवेदनों का किया गया निराकरण

नर्मदापुरम (निप्र)। कलेक्ट्रेट कार्यालय में जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें अपर कलेक्टर नर्मदापुरम श्री देवेंद्र कुमार सिंह ने अधिकारियों के साथ जनसामान्य की समस्याओं पर गंभीरता से सुनवाई कर उनका निराकरण किया। जनसुनवाई में आए 60 आवेदनों पर सुनवाई की गई। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को प्राप्त आवेदनों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। साथ ही पिछली जनसुनवाई में आए आवेदनों के निराकरण की स्थिति की जानकारी भी ली। जनसुनवाई में संयुक्त कलेक्टर श्री फरहीन खान सहित अन्य सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहें।

जनसुनवाई में अधिकारियों ने सुनी नागरिकों की समस्याएं

हरदा (निप्र)। जनसुनवाई कार्यक्रम के तहत शासकीय कार्यालयों में नागरिकों की समस्याएं सुनी जाती है। इसी क्रम में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री रोहित सिसोनिया ने जिला पंचायत के सभाकक्ष में उपस्थित नागरिकों की समस्याएं सुनी और उनके निराकरण के लिये अधिकारियों को निर्देश दिये। इस दौरान संयुक्त कलेक्टर श्री के.सी. परते सहित अन्य विभागीय अधिकारी भी मौजूद थे। जनसुनवाई में सीईओ श्री सिसोनिया को आवेदन देकर ग्राम बन्दीमुहाड़िया निवासी आयुष वर्मा ने बताया कि उसके पिता पंचायत सचिव थे। उनके अचानक निधन के पश्चात अनुकम्पा नियुक्ति अभी तक नहीं मिली है, जिस पर उन्होने आवेदक को पात्रता अनुसार अनुकम्पा नियुक्ति दिलाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये। इसके अलावा अन्य आवेदकों ने भी जनसुनवाई में अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किये, जिस पर सीईओ श्री सिसोनिया ने संबंधित अधिकारियों को आवेदनों का समय सीमा में निराकरण के निर्देश दिये।

कलेक्टर श्री दुबे ने वीडियो कॉफ्रेंस के माध्यम से की विकसित भारत संकल्प यात्रा की तैयारियों की समीक्षा

रायसेन (निप्र)। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत रायसेन जिले के समस्त नगरीय निकायों के वार्डो तथा ग्राम पंचायतों में यात्राओं तथा शिविरों का आयोजन किया जाएगा। कलेक्टर श्री अरविंद दुबे ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में वीडियो कॉफ्रेंस के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के आयोजन हेतु की जा रही तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए। कलेक्टर श्री दुबे ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जिले में आठ आईईसी वेन नगरीय निकायों तथा ग्राम पंचायतों में पहुंचकर केन्द्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार करेगीं।

आईईसी वेन में उपलब्ध ऑडियो विजुअल एड, ब्रोशर, पम्पलेट, बुकलेट इत्यादि से सूचनाओं और जानकारियों को आमजन तक पहुँचाया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों से जनपदवार बनाए गए रूट चार्ट की जानकारी लेते हुए कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा में अधिक से अधिक नागरिकों की भागीदारी हो और जरूरतमंदों तक योजनाओं का लाभ पहुंचे, यह सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर श्री दुबे ने निर्देश दिए कि विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम स्थलों पर स्वास्थ्य विभाग तथा आयुष विभाग द्वारा स्वास्थ्य शिविर

आयोजन हेतु सभी व्यवस्थाएं की जाएं। साथ ही कार्यक्रम स्थलों पर महिला बाल विकास विभाग, बैंक, स्व-सहायता समूहों, कृषि, उद्यानिकी, जल जीवन मिशन आदि के स्टॉल लगाकर योजनाओं की जानकारी दी जाएगी।

इसके लिए भी सभी तैयारियां पूर्ण कर ली जाएं। कार्यक्रम स्थलों पर तकनीकी सत्र भी आयोजित होंगे जिनमें कृषि कार्यो में ड्रोन के उपयोग का प्रदर्शन, मिट्टी परीक्षण, प्राकृतिक और उन्नत खेती की जानकारी दी जाएगी। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला पंचायत सीईओ श्रीमती अंजू पवन भदौरिया, अपर कलेक्टर श्री अभिषेक दुबे सहित जिला अधिकारी उपस्थित रहे।

वीडियो कॉफ्रेंस के माध्यम से अनुभागों से एसडीएम, जनपद सीईओ, सीएमओ सहित संबंधित अधिकारी भी शामिल हुए।

विश्व-स्तरीय सर्वसुविधा संपन्न सीएम राइज विद्यालयों में दी जायेगी उच्च गुणवत्तायुक्त

सीहोर (निप्र)। सीएम राइज विद्यालय सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जिसका मुख्य लक्ष्य अनुकरणीय रूप से बच्चों के सीखने की प्रक्रियाओं को निर्धारित करना, विद्यार्थियों की सीखने की निरंतरता और शिक्षकों तथा विद्यार्थियों के बीच सहज जुड़ाव है। सीएम राइज स्कूल विद्यार्थियों के सम्पूर्ण विकास का विजन एवं विद्यार्थियों को 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाने के मिशन के साथ साहसी, उत्कृष्ट, सत्य निष्ठ तथा सभी के प्रति सम्मान और करूणा से युक्त विद्यार्थियों को गढ़ेगा। विश्व स्तरीय आधारभूत संरचनासीएम राइज स्कूलों में उच्च गुणवत्तायुक्त विश्व-स्तरीय आधारभूत संरचना के साथ स्मार्ट क्लास में शिक्षा दी जायेगी। इन स्कूलों में पाठ्येत्तर गतिविधियों जैसे- संगीत, नृत्य, कला, खेल, व्यायाम एवं अन्य शिल्प के लिए आवश्यक उपकरण एवं सुसज्जित स्थान होंगे। विश्व-स्तरीय सर्वसुविधायुक्त भवन, किचन एवं कैफेटेरिया व्यवस्था, प्राथमिक चिकित्सा स्वास्थ्य सुविधा, कौशल विकास शिक्षा, स्मार्ट एवं डिजिटल कक्षाएँ, पूर्ण समृद्ध आधुनिक प्रयोगशालाएँ, लाइब्रेरी, कला-संगीत, खेलकूद आदि की व्यवस्था होगी। नर्सरी एवं पूर्व प्राथमिक शिक्षा, व्यावसयिक शिक्षा एवं नीट, क्लेट, जेईई आदि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कराई जायेगी।

विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण : सीएम राइज स्कूल में विद्यार्थियों की आवश्यकताओं, क्षमताओं, रूचियों और सीखने की शैलियों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए एक सुरक्षित, आनंदमयी और समावेशी स्थान पर शिक्षा दी जाएगी। यह ऐसा दृष्टिकोण है जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी की विशेषताओं को पहचान कर शिक्षित किया जाएगा।

विद्यार्थी के समग्र विकास के लिए शिक्षा : सीएम राइज स्कूल में विद्यार्थियों के समग्र विकास पर ध्यान केन्द्रित करते हुए शिक्षा दी जायेगी। इससे विद्यार्थी की बौद्धिक, शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक क्षमताओं का विकास होगा और वे जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम बन सकेंगे। सीएम राइज स्कूल प्रदेश के विकास एवं बेहतर भविष्य गढ़ने में मील का पत्थर साबित होंगे।

पेयजल आरक्षित करने के निर्देश

विदिशा (निप्र)। कलेक्टर श्री उमाशंकर ने जिले में औसतन से कम हुई वर्षा को ध्यानगत रखते हुए ग्रीष्मकाल के दौरान पेयजल संकट स्थिति निर्मित ना हो इसके लिए पूर्व में प्रबंध सुनिश्चित कराते हुए जिले के सगड़ बाह परियोजना एवं कोठा बैराज परियोजना में पेयजल संरक्षित करने के आदेशित पत्र संबंधित परियोजना के कार्यपालन यंत्री व परियोजना प्रशासक को जारी किए है। कलेक्टर श्री भार्गव के द्वारा जारी पत्र में उल्लेख है कि सगड़ बाह परियोजना से बासौदा शहरी क्षेत्र के लिए तथा कोठा बैराज से कुरवाई शहरी क्षेत्र के लिए पेयजल आरक्षित की आवश्यकता को ध्यानगत रखते हुए संबंधित बांध में जल आरक्षित करने के तमाम प्रबंध सुनिश्चित किए जाएं।

शासकीय विद्यालय के विद्यार्थियों के लिये चिकित्सा शिक्षा में 5 फीसदी आरक्षण

रायसेन (निप्र)। शासकीय विद्यालय के विद्यार्थी को सभी शासकीय एवं निजी महाविद्यालय में एमबीबीएस एवं बीडीएस के लिये स्वीकृत कुल सीट्स में से 5 प्रतिशत सीट्स आरक्षित की गई हैं। महिला अभ्यर्थी को सभी महाविद्यालयों में सभी पाठ्यक्रम में 30 प्रतिशत आरक्षण, दिव्यांग अभ्यर्थी को सभी महाविद्यालयों में सभी पाठ्यक्रम में 5 प्रतिशत तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अभ्यर्थी और सैनिक अभ्यर्थी को केवल शासकीय महाविद्यालय में एमबीबीएस एवं बीडीएस के लिये कुल सीट्स का 3-3 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। महिला, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सैनिक, दिव्यांग, अनिवासी भारतीय प्रवर्ग एवं शासकीय विद्यालय के विद्यार्थी शामिल हैं।

इसी प्रकार जोड़े गये उप-नियम अनुसार शासकीय विद्यालय से अभिप्रेत है कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा संचालित शासकीय विद्यालय के विद्यार्थियों में ऐसे विद्यार्थी, जिन्होंने शासकीय विद्यालय में कक्षा-6 से 12 वीं तक नियमित अध्ययन कर परीक्षा उत्तीर्ण की हो अथवा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के माध्यम से प्रवेश के आधार पर कक्षा-1 से 8 तक निजी विद्यालयों में अध्ययन करने के बाद शासकीय विद्यालय में कक्षा-9 से 12वीं तक नियमित अध्ययन कर परीक्षा उत्तीर्ण हो, को शामिल किया गया है।

विकसित भारत संकल्प यात्रा का मुख्य उद्देश्य योजनाओं का लाभ वंचितों को दिलाना: कलेक्टर

विदिशा (निप्र)। कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव ने समयावधि.पत्रों की समीक्षा में सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के सफल क्रियान्वयन का समन्वय के साथ कार्य किया जाना सुनिश्चित करें। नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संकल्प यात्रा आयोजन किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों के लिये विकसित भारत संकल्प यात्रा की तिथि शीघ्र शासन से प्राप्त होने वाली है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार की योजनाओं का लाभ वचितों को दिलाने के साथ साथ राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ भी अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों को दिलाया जाने। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि संकल्प स्थान पर मुख्य विभाग शिविर आयोजित करें ताकि अपने अपने विभाग की योजनाओं का प्रचार प्रसार, हो सके और पात्र हितग्राहियों को लाभावित किया जा सके।

जनपद सीईओ संकल्प यात्रा पर अधिक फोकस करें

कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव ने बैठक में निर्देश दिये कि ग्रामीण क्षेत्रों में जनपद पंचायतों के सीईओ विकसित भारत संकल्प यात्रा पर अधिक फोकस करें और यात्रा को अच्छे तरीके से कड़ी मेहनत कर सफल बनायें। लोगों को जोड़ने के लिये स्थानीय स्तर की भजन मण्डलियों को आमंत्रित किया जाये। इसी तरह जनप्रतिनिधियों को भी यात्रा में आमंत्रित किया जाये। जनपद स्तर पर सीईओ नोडल अधिकारी रहेंगे। सभी अधिकारी आपसी समन्वय स्थापित कर यात्रा को बेहतर ढंग से सफल बनाकर भारत सरकार एवं राज्य सरकार की यात्रतेजनाओं का चचितों को लाभ दिलाना सुनिद्धित करें। कलेक्टर ने समस्त राजस्व अनुविभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये कि ग्रासरूट लेवल की बैठक लेकर सम्बन्धितों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी करें। विकसित भारत संकल्प यात्रा का मुख्य उद्देश्य बचित व्यक्ति तक पहुंचना और सरकार यह सुनिधित करावे कि प्रमुख योजनाओं का लाभ। लक्षित लाभार्थियों खासतौर से वंचित व आकांक्षी लोगों तक समयबद्ध तरीके से लाभ पहुंचे। इसी तरह जन. सामान्य में योजनाओं का प्रचार प्रसार एवं जागरूकता पैदा करना और बचितों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना।

इटारसी सिविल अस्पताल एनकास में हुई सर्टिफाइड

नर्मदापुरम (निप्र)। डॉ श्यामाप्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल मंगलवार को घोषित हुये नेशनल क्वालिटी एंश्योरेस स्टैण्डर्ड एनकॉस के परिणाम के अंतर्गत 93.43 प्रतिशत से नेशनल क्वालीफाइड सर्टिफिकेट प्राप्त एवं मुस्कान कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिशत नेशनल क्वालीफाइड सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। दिनांक 18 से 20 सितंबर 2023 को भारत सरकार द्वारा 2 सदस्यीय नेशनल एसेसर द्वारा 03 दिवस संस्था में भ्रमण किया गया था। एनकॉस के अंतर्गत संस्था के 12 विभागों में चेकलिस्ट अनुसार 8 भागों में बॉटकर निरीक्षण दल द्वारा निरीक्षण किया गया। जिसमें सभी 12 विभागों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, डॉ. एसपीएम सिविल अस्पताल इटारसी में मुस्कान नेशनल एसेस्टमेंट में 04 विभागों में संचालित एनबीएसयू विभाग को प्रदेश का पहला मुस्कान नेशनल सर्टिफाइड एनबीएसयू घोषित हुआ। एनकॉस एवं मुस्कान सर्टिफाइड प्राप्त करने हेतु राज्य स्तर से डॉ. प्रमोद गोयल, डॉ. विवेक मिश्रा, डॉ. संदीप शर्मा, राधिका मेडम एवं जिला स्तरीय टीम से सीएमएचओ डॉ. दिनेश देहलवार, डीएचओ डॉ रमेश वर्मा, डीक्यूएम डॉ आलिया रूखसार, जिला मेंटर डॉ जी.आर. करोड़े, डॉ, मिलन सोनी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। सिविल अस्पताल के अधीक्षक डॉ. आर.के. चौधरी के नेतृत्व में आरएमओ डॉ. विकास जैधपुरिया, डॉ. आभा जैन, डॉ. कमलेश कुमरे, डॉ. दिनेश यादव, डॉ. मंजू चौधरी, डॉ विवेकचरण दुबे, डॉ. आभा दुबे, डॉ. अर्पित त्रिवेदी, डॉ. आशीष पटैल, डॉ. प्रियांक मिश्रा, डॉ. अभिषेक अग्रवाल, डॉ. जेक जकारिया निकसन, डॉ.प्रेसी युसुफदास, डॉ.उदित भटट, डॉ. नीतेश दीवान, संस्था की एसेसर श्रीमति अंजलि पाठक, समस्त नर्सिंग ऑफीसर ट्यूटर ऑफीसर एवं विशेष सहयोग में समाजसेवी संजय मिहानी, टीकाकरण शाखा के समस्त कर्मचारी, स्टोर शाखा से लोकेश ठाकुर, शिखर वर्मा, समस्त 12 विभागों के नोडल अधिकारी, ब्लड बैंक एवं लेब के सब नोडल अधिकारी, समस्त कम्प्यूटर ऑपरेटर, समस्त पैरामेडिकल व कार्यालयीन स्टॉफ, समस्त वार्ड वॉय, समस्त सफाई कर्मचारी, सपोर्ट स्टॉफ, किचिन कर्मचारी, पंप एवं इलेक्ट्रिशन सहित अन्य सभी अधिकारी कर्मचारियों ने पूर्ण लगन एवं कार्यनिष्ठा से कार्यदायित्व निभाया।

दैनिक
सद्भावना पाती

...प्राणियों में सद्भावना हो...

गजेंद्र वर्मा को मिली प्रदेश कांग्रेस महामंत्री की जवाबदारी

इंदौर। मप्र में उम्मीद से उलट परिणाम पाने वाली कांग्रेस, अब युवा और प्रतिभाशाली नेताओं की पूछ परख कर रही है इंदौर में कई प्रभारी शहर

कांग्रेस अध्यक्ष नियुक्ति के बाद विधानसभा 4 के प्रबल दावेदार कुश्ती खिलाड़ी पहलवान गजेंद्र वर्मा को प्रदेश कांग्रेस में महामंत्री बनाया गया है। बीजेपी ने जिस तरह से तीसरी पंक्ति के नेता को मुख्यमंत्री बनाया है शायद इसी से सबक लेकर कमलनाथ ने अब दूसरी कतार के नेताओं को आगे करना शुरू कर दिया और शहर में कार्यवाहक अध्यक्ष के बाद अब प्रदेश नेतृत्व में युवाओं को नवाजा जा रहा है।

नियुक्ति पर श्री वर्मा ने कहा मै पार्टी का सच्चा और ईमानदार कार्यकर्ता हूँ पार्टी जो भी जवाबदारी देगी उसे निभाऊंगा कोई भी पद ताकत के लिए नहीं बल्कि जिम्मेदारी के लिए दिया जाता है, कांग्रेस लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी।हम युवा मतदाताओं को कांग्रेस से जोड़कर जमीन पर कार्य करेंगे।

निगम में कर्मचारी समय पर आने लगे

इंदौर। निगम कार्यालय में कई अधिकारी कर्मचारी निर्धारित समय सुबह 10.30 बजे नहीं पहुंचते। इससे कामकाज प्रभावित होने के साथ शिकायत कताओं को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोगों की परेशानी को दूर करने निगम आयुक्त हर्षिका सिंह ने आदेश जारी किए थे कि सभी अधिकारी-कर्मचारी तय समय पर कार्यालय पहुंचें। इसके बाद भी कार्यालय में प्रवेश करने पर उचित कार्रवाई की जाएगी।

आदेश का असर यह हुआ कि निगम परिसर में अधिकारियों की आमद शुरू हो गई। कई अधिकारी दोपहर 12 बजे तक कार्यालय पहुंचते थे। समय पर अधिकारी पहुंचने से मातहतों को दिनभर का कामकाज सौंपा गया।

शिवाजी मार्केट के लिए फिर नोटिस

इंदौर। विधानसभा चुनाव के पहले निगम ने शिवाजी मार्केट के दुकानदारों को बेदखली का नोटिस जारी किया था। नोटिस के बाद दुकानदारों ने दबाव प्रभाव बनाकर कार्रवाई रुकवा दी। चुनाव निपटते ही निगम में कामकाज सामान्य हो गए। अब एक बार फिर दुकानदारों को नोटिस दिया जाएगा। यहां 49 से अधिक दुकानें संचालित होती है। इन दुकानदारों को नंदलालपुरा स्थित काम्प्लेक्स में स्थान दिया जाना प्रस्तावित है। दुकान के स्थान पर निगम सड़क बनाएगा।

17 दिसंबर को एनआरआई सम्मेलन

इंदौर। नगर निगम में कामकाज सामान्य होने के बाद एक बार फिर एनआरआई(प्रवासी भारतीय सम्मेलन) का आयोजन होने जा रहा है। यह चार दिनी कार्यक्रम ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आगामी 17 दिसम्बर को होगा। आयोजन में शामिल होने 190 मेहमानों ने पंजीयन कराया है। इसमें निगम ने 250 मेहमानों को आने का निमंत्रण दिया था। जानकारी के मुताबिक, सम्मेलन को लेकर कार्यक्रम स्थल पर एक-दो दिन में तैयारियां शुरू की जाएगी। पिछली बार जनवरी में सम्मेलन बुलाया गया था। उस दौरान सम्मेलन में आने वाले मेहमानों का सारा खर्च राज्य शासन ने वहन किया था, इस बार निगम मेहमानों का आने का खर्च वहन नहीं करेगा। सम्मेलन में जापान, अमेरिका, आस्ट्रेलिया, आयरलैंड, बहरीन, कनाड़ा, स्वीडन आदि देशों के मेहमान आए हैं। मेहमानों को चार दिन होटलों में ठहराया जाएगा। उन्हें रणजीत हनुमान मंदिर के समीप बन रहे अयोध्या के राम मंदिर की प्रतिकृति के साथ 56 दुकान का भ्रमण कराया जाएगा। मेहमानों से समस्याओं के निराकरण के साथ ही शहरहित में उनके योगदान पर नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारी चर्चा करेंगे।

पुलिस पंचायत में बुजुर्गों की समस्या का निराकरण

इंदौर। विधानसभा चुनाव के चलते दो माह पहले पुलिस पंचायत को विराम दिया गया था। बुधवार को फिर कलेक्टोरेट के सेटेलाइट भवन में पंचायत शुरू हुई तो कई बुजुर्ग अपनी पीड़ा लेकर पहुंचे। अधिकारियों ने उनकी पीड़ा सुनकर निराकरण कराया। पंचायत में 7 प्रकरण आए थे, जिन्हें अधिकारियों ने गंभीरता से सुनते हुए 5 का निराकरण कर शेष 2 को अगली बैठक में रखा जाएगा। पहले मामले में अन्नपूर्णा के 68 वर्षीय बुजुर्ग ने बताया कि बेटे-बहू द्वारा प्रताड़ित करते हैं, जिस पर दोनों पक्षों को बुलाया। समझाइश के बाद दोनों पक्ष में सहमति बनी कि भविष्य में विवाद नहीं करेंगे। दूसरे प्रकरण में एरोड्रम के 69 वर्ष के बुजुर्ग ने बेटे द्वारा मकान पर कब्जा बेदखल करने की शिकायत की। समझाइश के बाद बेटे ने मां के चरण स्पर्श कर माफी मांगते हुए विवाद नही करने का आश्वासन दिया। तीसरा मामला परदेशीपुरा की 82 वर्ष की बुजुर्ग ने किराएदार की शिकायत की कि वह किराया नहीं दे रहा है। टीम की समझाइश के बाद किराएदार ने दोनों के बीच उपजे विवाद का समाधान करने की सहमति जताई। चौथे मामले में छत्रीपुरा की 67 वर्ष की बुजुर्ग ने पुत्र की शिकायत की कि वह शराब पीकर गाली-गलौज करता है। बेटे को समझाइश मिलने पर आवेदिका संतुष्ट हुई।

नशाखोरों ने फूड डिलीवरी बाय को चाकू मारकर उसकी बाइक छीनी

इंदौर। नशे की लत पूरी करने के लिए फूड डिलीवरी बाय ने पैसे नहीं दिए तो उसकी बाइक छीनकर ले गए। घटना को दो बदमाशों ने अपने नाबालिग साथी के साथ अंजाम दिया था। इस दौरान डिलीवरी बाय को जांघ में चाकू भी मारा था। मामला एरोड्रम थाना क्षेत्र का है।

एमवाय हॉस्पिटल का ब्लड बैंक होगा हाईटेक, ट्रैकर डिवाइस लगाकर रक्त की पोली बैग पर निगरानी रखेगा ब्लड बैंक

इंदौर। नए साल में एमवायएच ब्लड बैंक को अंतरराष्ट्रीय स्तर के मापदण्डों के हिसाब से हाईटेक किया जाएगा।अब ब्लड बैंक को जहां एक बार में एक साथ कई ब्लड ग्रुप की क्रॉस मैचिंग के लिए ऑटोमैटिक मशीन मिलेगी, वहीं एमवायएच से बाहर अन्य जरूरतमंद मरीजों के लिए ब्लड बैंक से दिए जाने वाले ब्लड बैग यानि खून की थैलियों में ब्लड की क्वालिटी सिक्यूरिटी के लिए लोकेशन ट्रैकर डिवाइस लगाया जाएगा। इस के जरिये ब्लड बैंक अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लड की मेडिकल टेम्प्रेचर सिक्यूरिटी और लोकेशन की मॉनिटरिंग यानि निगरानी कर सकेगा। यह लोकेशन ट्रैकर डिवाइस रेडियो फ्रीक्वेंसी सिस्टम के माध्यम से ब्लड बैंक से कनेक्ट रहेगा। इस लोकेशन ट्रैकर से यह पता लगाया जा सकेगा कि ब्लड बैंक से रवाना हुआ ब्लड कितनी देर तक कहां-कहां पहुंचा व मरीज को कितनी देर बाद यह ब्लड चढ़ाया गया। ब्लड बैंक प्रमुख डॉक्टर अशोक यादव ने बताया कि संभागायुक्त की पहल पर अब ब्लड बैग्स में लोकेशन ट्रैकर डिवाइस लगाए जाएंगे। यह लोकेशन ट्रैकर डिवाइस रेडियो फ्रीक्वेंसी सिस्टम आईडी के माध्यम से ब्लड बैंक से कनेक्ट रहेंगे। इसके माध्यम से ब्लड बैंक प्रबंधन को कम्प्यूटर स्क्रीन पर यह जानकारी मिलती रहेगी कि ब्लड रेफ्रिजरेटर से निकाले जाने के बाद कितने तापमान में कितनी देर बाहर सफर करता रहा।

डॉक्टर यादव के अनुसार मेडिकल गाइडलाइन के हिसाब से उचित और जरूरी टेम्प्रेचर के लिए ब्लड बैग को हमेशा रेफ्रिजरेटर यानि फ्रीज में ब्लड की सुरक्षा के लिए तय

तापमान के अंदर रखा जाता है। ज्यादा हाई टेम्प्रेचर में ब्लड के खराब होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। फ्रिज से बाहर निकालने के बाद ब्लड आधे घण्टे में जरूरतमंद मरीज के हॉस्पिटल तक जरूर पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि फ्रिज से ज्यादा देर तक बाहर रहने वाले ब्लड के मेडिकल कन्टेंट में बदलाव आने से मरीज की जान को खतरा भी हो सकता है। इसलिए अब ब्लड बैग में लोकेशन डिवाइस ट्रैकर लगाने की प्लानिंग पर काम शुरू कर दिया गया है।

एक घंटे का काम अब 20 मिनट में

यह ब्लड बैंक टेक्नोलॉजी वाली हाईटेक मशीनों के अभाव में पुराने उपकरण सीमित संसाधनों के साथ ओल्ड मैन्युअल सिस्टम से यानि पारंपरिक तरीके से काम करता आ रहा है। इसलिए समय की बचत करने और ब्लड पर निगरानी रखने के ब्लड बैंक को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर के मापदंडों के हिसाब से हाईटेक करने के चलते ब्लड बैंक में ऑटोमैटिक ब्लड ग्रुप क्रॉस मैचिंग मशीन लगवा रहे हैं, जिससे एक साथ कई ब्लड ग्रुप की क्रॉस मैचिंग जांच सिर्फ 20 मिनट में हो सकेगी। फिलहाल जांच करने में लगभग 1 घण्टे का समय लगता है।

ब्लड रखने के लिए नए रेफ्रिजरेटर

पहले यह ब्लड बैंक एमवायएच की पैथोलॉजी लैबोरेट्री में अटैच थी। कई सालों बाद इसे पैथोलॉजी से अलग कर ब्लड बैंक का स्वतंत्र विभाग बनाया गया है। तब से अब तक ब्लड बैग रखने के लिए 6 अमेरिकन ब्लड रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। मगर अब हाईटेक सिस्टम के लिए और नए ब्लड रेफ्रिजरेटर खरीदेंगे।

एक ब्लड बैग पर 30 रुपए खर्च आएगा

प्रदेश में सबसे ज्यादा ब्लड संग्रह करने वाले सबसे बड़े और सबसे पुराने इस ब्लड बैंक का अंतरराष्ट्रीय मापदंड के हिसाब से अत्याधुनिक करण किया जा रहा है। संभागायुक्त की पहल और दिशा निर्देश पर इस योजना पर काम शुरू कर दिया गया है। एक ब्लड बैग यानि खून की थैली पर लोकेशन ट्रैकर डिवाइस लगाने में लगभग 30 रुपए का खर्च आएगा।

-डॉक्टर अशोक यादव,
प्रमुख अधिकारी, एमवायएच ब्लड बैंक

इंदौर नगर निगम का आज से बाजारों में कब्जे हटाने का बड़ा अभियान

200 कर्मचारियों की टीमें कब्जे हटाने में जुटेंगी

इंदौर। शहर के सभी प्रमुख बाजारों की बदहाल स्थिति और यातायात का कबाड़ा होने के चलते निगम आज से कार्रवाई और मुनादी का अभियान शुरू कर रहा है। ठेले, खोमचे और सडक़ घेरकर व्यापार करने वालों पर सख्ती की जाएगी। इसके लिए झोनलों की टीमें भी आज से कई जगह कार्रवाई करेंगी और यातायात पुलिस और प्रशासन के अफसरों के नेतृत्व में भी बड़ा अभियान शुरू किया जाएगा, ताकि सडक़ों से कब्जे हटाए जा सकें।

महापौर पुष्यमित्र भार्गव और राजस्व समिति प्रभारी निरंजन सिंह चौहान आज कई प्रमुख बाजारों का निरीक्षण करने भी अफसरों के साथ जाएंगे, ताकि वहां स्थिति पर निर्णय लिया जा सके। शहर के सभी मुख्य बाजारों की हालत बदतर है और दुकानदारों ने फुटपाथों पर भी कब्जे कर लिए हैं, जिसके चलते पैदल चलने वालों के लिए जगह नहीं बचती है।

कुछ जगह बच जाती है तो उस जगह पर फेरी वाले और ठेले, खोमचे वालों के कब्जे हो जाते हैं, जिसके चलते बाजारों की यातायात व्यवस्था का पूरी तरह तहस नहस हो जाता है। सभी रिमूवल अधिकारियों को बैठक के दौरान निर्देश दिए गए थे कि आज से शहर भर में अभियान चलाकर ठेले, खोमचे वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करें। इसके लिए निगम रिमूवल विभाग की टीमें अलग-अलग क्षेत्रों में सुबह 11 बजे से निकलेंगी। पिछले कई दिनों से निगम की रिमूवल टीमों द्वारा मुनादी भी की जा रही थी, मगर उसके बावजूद कब्जे नहीं हटे। नगर निगम अधिकारियों के मुताबिक राजबाड़ा, इमामबाड़ा, पीपली बाजार, बर्तन बाजार, बजाज खाना चौक, सीतलामाता बाजार, जवाहर मार्ग, गोराकुंड, शिव विलास पैलेस, कृष्णपुरा की नई रोड, सपना-संगीता रोड, टॉवर चौराहा, महू नाका, लालबाग रोड से लेकर हरसिद्धि, कलेक्ट्रेट रोड और मालवा मिल, पाटनीपुरा, भमोरी, सदर बाजार रोड, जेल रोड, एमजी रोड के साथ-साथ रानीपुरा, सियागंज, सरवटे, छोटी ग्वालटोली आदि क्षेत्रों में टीमें कार्रवाई के लिए जाएंगी।

1 वर्ष के लिए बंद होगा रेती मंडी का रेलवे क्रासिंग, 25 करोड़ की लागत से बनेगा रेलवे ओवरब्रिज

रेती मंडी ओवरब्रिज का काम अब पकड़ेगा तेज गति

इंदौर। रेल ओवरब्रिज के निर्माण के लिए पीडब्ल्यूडी ने रेती मंडी रेलवे क्रॉसिंग को बंद कर दिया है। अब वाहन चालक राजेंद्र नगर ओवरब्रिज का उपयोग करके इधर से उधर आ-जा सकेंगे। रेती मंडी रेलवे क्रॉसिंग को एक साल के लिए बंद किया गया है। तब तक लोगों को यह परेशानी उठाना पड़ेगी और घूमकर आना-जाना करना पड़ेगा। लगभग 25 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे इस ओवरब्रिज के पांच पिलर की फाउंडेशन तैयार हो चुकी है, लेकिन बाकी के पिलर का काम शुरू करने के लिए अब रेलवे क्रॉसिंग बंद करना जरूरी है। पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन यंत्री (ब्रिज) दीपेश गुप्ता ने बताया कि तीन भुजाओं वाले इस ब्रिज की एबी रोड तरफ वाली भुजा टू लेन और राजेंद्र नगर-राऊ तरफ वाली भुजाएं फोर-फोर लेन की होंगी। ट्रैफिक डायवर्सन की सूचना पहले ही पुलिस प्रशासन को दी जा चुकी है। क्रॉसिंग को बंद कर काम तेजी से किया जाएगा, ताकि एक साल में पुल बनकर तैयार हो जाए।

दो अन्य ब्रिजों के लिए भी होगा डायवर्सन

पीडब्ल्यूडी जल्द ही बाणगंगा और लक्ष्मीबाई नगर माल गोदाम रेलवे क्रॉसिंग पर भी ओवरब्रिज का निर्माण शुरू करने वाला है। दोनों ब्रिजों के लिए सॉइल और रॉक टेस्टिंग का काम पूरा हो चुका है। ड्राइंग-डिजाइन मंजूर होते ही पिलर निर्माण का काम शुरू हो जाएगा।

15 से 30 दिसंबर तक इंदौर-उज्जैन के बीच ब्लॉक, 4 ट्रेनें निरस्त, 12 डायवर्ट

इंदौर। उज्जैन सेक्शन में बरलई से मांगलिया के बीच डबल ट्रैक का काम चल रहा है। इसके तहत रेलवे ने 15 से 30 दिसंबर तक मेगा ब्लॉक घोषणा की है। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार चार पैसेंजर और डेमू ट्रेनें निरस्त की गई। इसके अलावा 12 से ज्यादा ट्रेनें डायवर्ट रहेंगी। चार ट्रेनें शॉर्ट टर्मिनेट की गई हैं। ये ट्रेनें वाया उज्जैन फतेहाबाद-चंद्रावतीगंज-रतलाम होकर चलेगी। जानकारी के अनुसार 19 और 26 दिसंबर को रामेश्वरम-फिरोजपुर एक्सप्रेस वाया उज्जैन फतेहाबाद चंद्रावतीगंज-रतलाम होकर चलेगी। 19 एवं 26 दिसंबर को रामेश्वरम-फिरोजपुर

एक्सप्रेस वाया उज्जैन फतेहाबाद चंद्रावतीगंज-रतलाम होकर चलेगी। 18 और 25 दिसंबर को इंदौर-उधमपुर एक्सप्रेस वाया रतलाम फतेहाबाद चंद्रावतीगंज और रतलाम व नागदा होकर चलेगी। महू-रतलाम और इंदौर-उज्जैन के बीच ट्रेनें निरस्त होने से सबसे ज्यादा परेशानी लोकल अप-डाउनर्स को होगी। करीब 7 हजार लोगों को अब 15 दिनों के लिए वैकल्पिक साधन देखना होंगे। नर्मदा एक्सप्रेस उज्जैन से चलेगी। ऐसे में यात्रियों को इंदौर उज्जैन तक जाना होगा। उज्जैन से वापस वैकल्पिक साधनों से आना होगा। कोटा एक्सप्रेस मक्सी से चलेगी। यात्रियों को मक्सी आना-जाना होगा। दोनों ट्रेनों से दो हजार से ज्यादा यात्री प्रभावित होंगे।

उत्तर रेलवे में मेगा ब्लॉक

- उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल में बाराबंकी-अयोध्या कैंट-शाहगंज-जफराबाद खंड में दोहरीकरण के लिए प्रस्तावित मेगा ब्लॉक के कारण रतलाम से आने-जाने वाली 11 से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। इसमें इंदौर-पटना एक्सप्रेस ट्रेन भी प्रभावित होगी। 16 दिसंबर से 13 जनवरी तक इंदौर-राजेंद्रनगर पटना एक्सप्रेस ट्रेन वाया लखनऊ-सुल्तानपुर-जफराबाद होकर चलेगी। 18 दिसंबर से 15 जनवरी तक राजेंद्रनगर पटना-इंदौर एक्सप्रेस ट्रेन जफराबाद-सुल्तानपुर-लखनऊ होकर चलेगी।

इंदौर में आयोजित होगी विश्व की सबसे बड़ी आत्मरक्षा कार्यशाला 'रक्षम'

इंदौर। इंदौर स्थित एनजीओ ज्वाला (वॉयस ऑफ वूमेन) द्वारा एक अनूठी पहल के तहत विश्व की सबसे बड़ी आत्मरक्षा कार्यशाला ÷रक्षम÷ का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यशाला निर्भया दिवस के अवसर पर 16 दिसंबर को नेहरू स्टेडियम में सुबह 11 से दोपहर एक बजे तक आयोजित की जाएगी। ÷रक्षम÷ आत्मरक्षा प्रशिक्षण के माध्यम से 10 हजार महिलाओं को सशक्त बनाने और उनकी सुरक्षा करने के उद्देश्य से एक अभूतपूर्व कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यह कार्यशाला इंदौर को सिर्फ देश ही नही बल्कि विश्व स्तर पर एक नई पहचान दिलाते हुए विश्व रिकॉर्ड स्थापित करेगी। ज्वाला संस्था की संस्थापक डॉ. दिव्या गुप्ता ने बताया कि अपनी स्वच्छता के लिए मशहूर इंदौर शहर अब सुरक्षा के मामले में नया मानक स्थापित कर रहा है। दुनिया के सबसे बड़े आत्मरक्षा कार्यक्रम की मेजबानी करते हुए, इंदौर एक सुरक्षित समुदाय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करते हुए हजारों लोगों को सशक्त बनाने जा रहा है। यह पहल सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं है बल्कि सुरक्षित कल की ओर हम सभी का एक बड़ा कदम है। उन्होंने बताया कि ज्वाला (वॉयस ऑफ वूमेन) संस्था का उद्देश्य भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों की महिलाओं को आसानी से सुलभ संसाधनों के माध्यम से वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।

निर्भया दिवस पर आयोजित किए जा रहे भव्य कार्यक्रम हेतु अधिकारियों की ड्यूटी निर्धारित

इंदौर। इंदौर जिले में 16 दिसंबर को ज्वाला संस्था द्वारा निर्भया दिवस कार्यक्रम का भव्य आयोजन नेहरू स्टेडियम में किया जा रहा है। उक्त आयोजन के सुचारू रूप से संचालन एवं आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने हेतु कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी द्वारा अधिकारियों एवं कर्मचारियों के ड्यूटी निर्धारण के आदेश जारी किए गए हैं।

जारी आदेश अनुसार कार्यक्रम स्थल पर आगंतुकों के सुचारू रूप से आगमन एवं निर्गमन संबंधी संपूर्ण व्यवस्था का दायित्व तहसीलदार जूनी इंदौर श्री जगदीश रंधावा, नायब तहसीलदार जूनी इंदौर श्री कमलेश कुशवाह, नायब तहसीलदार राऊ श्री धीरेश सोनी, नायब तहसीलदार मल्हारगंज श्री ओंकार मनाग्रें, नायब तहसीलदार कनाड़िया सुश्री पूजा सिंह चौहान, नायब तहसीलदार भिचौली हप्सी श्री देवेंद्र कछावा को सौंपा गया है। ब्लॉक/पंक्ति में कार्यक्रम के दौरान आगंतुकों की सुविधा हेतु आवश्यक बैठक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए डिप्टी कलेक्टर श्रीमती प्रिया पटेल को समन्वयकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है। कार्यक्रम स्थल पर मंच संबंधी संपूर्ण व्यवस्था संयुक्त कलेक्टर श्रीमती रोशनी वर्धमान द्वारा देखी जाएगी। कार्यक्रम में आने वाली बसों को निश्चित समय और पूर्व से निर्धारित स्थान पर उपलब्ध कराना तथा संपूर्ण परिवहन व्यवस्था की मॉनिटरिंग करने का कार्य क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री प्रदीप शर्मा तथा डिप्टी कलेक्टर श्री चरणजीत सिंह हुड्डा द्वारा किया जाएगा।

इसी तरह स्वल्पहार व्यवस्था की जिम्मेदारी जिला आपूर्ति नियंत्रक श्री एम.एल मारू तथा डिप्टी कलेक्टर निधि वर्मा द्वारा की जाएगी। चिकित्सा व्यवस्था का दायित्व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्री बी.एस. सैत्या, चिकित्सा अधिकारी श्री अमित मालाकार तथा डिप्टी कलेक्टर श्रीमती सीमा कनेश मौर्य द्वारा किया जाएगा। विद्यालय तथा महाविद्यालय के प्रतिभागियों को उक्त आयोजन में लाने व ले जाने की व्यवस्था जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा की जाएगी। अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्रीमती सपना लोवंशी कार्यक्रम संबंधी समस्त व्यवस्थाओं की समन्वय अधिकारी रहेंगी। अपर कलेक्टर श्री राजेंद्र रघुवंशी कार्यक्रम के दौरान नेहरू स्टेडियम की आंतरिक व्यवस्थाओं के संपूर्ण प्रभारी रहेंगे तथा अपर कलेक्टर श्री रोशन राय कार्यक्रम के दौरान पार्किंग व्यवस्था एवं परिवहन व्यवस्था के संपूर्ण प्रभारी रहेंगे।

दैनिक सद्भावना पाती
इंदौर, शुक्रवार 15 दिसंबर, 2023

संपादकीय | अवैध प्रवासियों के आंकड़े जुटाना संभव नहीं

देश के विभिन्न इलाकों में रह रहे प्रवासियों की समस्या किस कदर गहरा चुकी है, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि आज केंद्र सरकार के सामने उनके सही आंकड़े जुटाना मुश्किल हो चुका है। यह एक तरह से शुरुआती दौर में किसी समस्या की अनदेखी से उपजी हुई मुश्किल है, जो आज जटिल शक्ल अख्तियार कर चुकी है।

सोमवार को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर बताया कि देश के विभिन्न हिस्सों में रह रहे अवैध प्रवासियों के आंकड़े जुटाना संभव नहीं है। इसलिए कि बहुत सारे लोग चोरी-छिपे देश की सीमा में दाखिल होते हैं। गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय नागरिकता कानून की धारा 6ए की वैधता पर सुनवाई कर रहा है, जो असम में अवैध प्रवासियों से संबंधित है।

हाल ही में अदालत ने केंद्र सरकार से इससे संबंधित आंकड़े मांगे थे कि देश में एक जनवरी 1966 से लेकर 25 मार्च 1971 तक कितने बांग्लादेशी नागरिकों को असम में भारतीय नागरिकता प्रदान की गई। साथ ही अवैध घुसपैठ रोकने के लिए अदालत ने सरकार की ओर से उठाए गए कदमों के बारे में भी पूछा था। शीर्ष अदालत की इस मसले पर केंद्र सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग के पीछे अवैध प्रवासियों की नागरिकता से लेकर उनकी वजह से पैदा होने वाली अन्य समस्याओं पर उठते सवालों का हल निकालने की कोशिश है। मगर अदालत को दिए गए केंद्र सरकार के जवाब से इस समस्या की जटिलता का अंदाजा लगता है।

सवाल है कि लंबे समय से देश के भीतर अलग-अलग इलाकों में उनकी पहचान तय कर पाने और उनके आंकड़े जुटाने में इस स्तर की

समस्या क्यों खड़ी हुई है! आए दिन अन्य देशों से लगती सीमा को सुरक्षित करने के लिए व्यापक धनराशि खर्च करने और हर स्तर पर उपाय करने के दावे के बीच यह कैसे मुमकिन हो पाता है कि कुछ लोग गुप्त तरीके से भारतीय सीमा में न केवल दाखिल हो जाते, बल्कि अपनी पहचान छिपा कर यहां की आबादी में घुलमिल जाते हैं?ऐसा नहीं है कि भारत में अवैध घुसपैठ के जरिए आने वाले पड़ोसी देशों के लोगों से उपजी समस्या नई है। भारत के पड़ोसी बांग्लादेश से अवैध तरीके से आए प्रवासी पिछले कई दशक से चिंता का कारण रहे हैं और कई बार इसने राजनीतिक मुद्दे की शक्ल भी अख्तियार की। यही नहीं, इस वजह से उपजे हिंसक टकराव में सैकड़ों लोगों की हत्या हो चुकी है। असल में शरणार्थियों से जुड़े मानवाधिकारों के पहलू भी कई बार सरकारों को ज्यादा सख्त होने से रोकते रहे हैं। कभी-कभार पड़ोसी देशों की ओर से देश में घुस आए लोगों को इक्का-दुक्का मामला मान कर नजरअंदाज कर दिया जाता है। मगर सच यह है कि वही अनदेखी बाद में एक जटिल रूप ले लेती है, जब उसकी वजह से कई तरह की मुश्किलें खड़ी होने लगती हैं। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि भारत में अवैध घुसपैठ और प्रवासियों की वजह से कई स्थितियों में आंतरिक सुरक्षा पर भी गंभीर प्रभाव डालता है। अदालत को दिए गए जवाब में अब केंद्र सरकार ने यह भी कहा है कि अवैध घुसपैठ को रोकने के मकसद से सीमा पर बाड़ लगाई जा रही है। लेकिन घुसपैठ को रोकने के लिए उठाए गए कदमों में इस स्तर की देरी की गई है कि उसकी वजह से देश के भीतर उपजने वाली समस्याओं का कोई ठोस हल निकालना एक बड़ी चुनौती है।

सोशल मीडिया से...

हर जिले में एक एक्सीलेंस कॉलेज खोला जायेगा. कुल 52 कॉलेज खोले जाएंगे. आदतन अपराधियों के लिए गृह मंत्रालय को कहा है कि ज़रूरत पड़ने पर उनकी जमानत निरस्त करना शुरू करें. 22 जनवरी को राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला विराजेंगे. अयोध्या की ओर जाने वाले मार्ग पर सरकार की तरफ से जगह-जगह रामभक्तों का स्वागत किया जायेगा।

मोहन यादव, सीएम मप्र

अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने साथ दिया होता तो नतीजे कुछ और होते समाजवादी पार्टी चाहती थी कि मध्य प्रदेश में वह कांग्रेस के साथ लड़े मगर कांग्रेस को लगता था कि सपा के साथ आने से कोई लाभ नहीं हो। हो सकता है कि इसीलिए उन्होंने मध्य प्रदेश के विधान सभा चुनाव में साथ छोड़ा।

अखिलेश यादव, सपा अध्यक्ष

यादवों की भगवान कृष्ण से तुलना की जाती है। हम लोग कृष्ण के वंशज हैं और यादव को मान-सम्मान मिल रहा है, यह अच्छी बात है।

तेज प्रताप यादव, मंत्री बिहार

यह सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद दो लोग अंदर कैसे आ गए और सुरक्षा में सेंध लगाई।

मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष

आज का कार्टून

कांग्रेस सुधरे, 'इंडिया' में सही सीट शेयरिंग हो तभी...

2024 लोकसभा कांग्रेस के लिए आखिरी मौका है। मैच अभी भी गया नहीं है। हाथमें है। बेरोजगारी, महंगाई, सरकारी शिक्षा, चिकित्सा आज भी बड़े इश्यू हैं। अगर इन्हें लेकर एक सीट पर एक लड़ लिए तो मोदी जी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। हिन्दू-मुसलमान कुछ नहीं चलेगा। बस सीट शेयरिंग इस भावना से हो जाए कि हमारी जैसे भी हो सीटें आए तो लड़ाई कांटे की हो सकती है। ज.दस साल हो गए लेकिन कांग्रेस अपनी कमियां खोजने में पूरी तरह असफल रही। और दस साल क्या कांग्रेस का पतन 2012 से शुरू हो गया था। दो तरीके होते हैं। एक बहुत सारे विकल्पों में बेहतरीन चुनना। दूसरा बहुतसारे विकल्पों में से कोई चुनना और उसे बेहतरीन प्रचारित करवा देना। मोदीजी राजनीति में दूसरा तरीका अख्तियार करते हैं। और कांग्रेस वह बहुत सारे विकल्पों के बारे में देखती ही नहीं है। अपनीपूर्व धारणा के अनुसार पहले से चयनित किए व्यक्ति थोप देती है।

शकील अख्तर

मध्य प्रदेश में मोहन यादव या उससे पहले छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय परकांग्रेस या राजनीतिक पर्यवेक्षक चाहे जितनी नाक भों सिकोड़ लें मगर उससेमोदी जी के सेहत पर क्या फर्क पड़ता है उन्होंने अपने पैमानों से अपना मुख्यमंत्री चुना है। या पैमाना भी किसी को अनावश्यक लग रहा हो तो अपनीमर्जी से। जब उनके पास ताकत है तो वह उसे क्यों नहीं बताएंगे भारत में जनता हमेशा से ताकतवर नेता चाहती है। इस आधार पर क्या कभी जनताको मोदी की आलोचना करते देखा है इससे पहले उन्होंने महाराष्ट्र मेंदेवेन्द्र फड़नवीस, हरियाणा में खट्टर, झारखंड में रघुवर दास, उत्तराखंडमें हारने के बाद भी धामी और भी जहां जिस पद पर चाहा अपने आधार परव्यक्ति को बिठाया। क्या इससे वे कमजोर हुए

दूसरी तरफ आप इस तरह देखिए कि अगर कांग्रेस छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश,राजस्थान जीत जाती, जो वह जीत ही रही थी, खुद ही अपनी गलतियों से हारी हैतो क्या वहां किसी नए को मुख्यमंत्री बनाने के बारे में सोच भी सकती थी।कमलनाथ ने खुद को भावी मुख्यमंत्री अनाउंस कर दिया था। बीच चुनाव में कहाकि प्रभारी जयप्रकाश अग्रवाल को हटाओ। वे आधी आधी रात तक घर जाकरकार्यकर्ताओं से मिलते हैं उन्हें सक्रिय कर रहे हैं यह सब ठीक नहीं है।और कांग्रेस ने उन जैसे वरिष्ठ नेता को बिना व्यक्तिगत रूप से सूचित किएएक प्रेस नोट के माध्यम से जिम्मेवारी से हटा दिया।

अब कोई कमलनाथ से पूछे कि अगर जयप्रकाश अग्रवाल ही रहते तो क्या हार इससेबड़ी हो जाती छत्तीसगढ़ में भी उससे थोड़े पहले पीएल पुनिया को हटाया गयाथा। कुमारी शैलजा को बनाया गया था। ऐसे ही राजस्थान में अजय माकन कोहटाकर सुखजिंदर सिंह रंधावा को बनाया गया था। अगर परिवर्तन के परिणामअच्छे निकलते तब तो कोई बात होती। मगर जब परिवर्तन ही बिना सही तरीके सेसोचे, ग्राउन्ड की स्थितियों को मालूम किए होते हैं तो वह उल्टे परिणामही देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना होती है। होना चाहिए। मगर उसका कोई उद्देश्यभी होना चाहिए। खासतौर से राजनीतिक दलों के लिए। राजनीतिक पर्यवेक्षक,लेखक, पत्रकार सैद्धांतिक आधारों पर बात करते हैं। कर सकते हैं। करना चाहिए।बड़े उसूलों के लिए, आदर्शों के लिए करते हैं। लोकतंत्र, तानाशाही,विभाजन की राजनीति नफरत के खिलाफ लिखते हैं। सही है। उनका काम है जनता कोलगातार जागरूक करते रहना। संवैधानिक मूल्यों पर हो रही चोटों से जनता कोअवगत कराना। देश और समाज को खोखला होने से बचाना। वे लिख सकते हैं। लिखरहे हैं। बोल रहे हैं। मगर क्या विपक्ष का काम भी बिल्कुल ऐसा ही है नहीं। उसे डेंट करना होताहै। चोट पहुंचाना। सत्ता पक्ष के उन पहलूओं पर हमला करना जिससे जनताउत्साहित हो। जनता को लगे कि उसकी बात है। उसे फायदा हो रहा है। सत्तापक्ष का एजेंडा ध्वस्त करना और अपने अजेंडे पर जनता को लाना। कांग्रेस फिलहाल इसमें सफल नहीं हो रही है। वह मोदी के एजेंडे में ही उलझजाती है। मुख्यमंत्री वे कहां से निकालकर लाए इस पर जनता नकारात्मक ढंग सेनहीं सोच रही है। मगर कांग्रेस इसमें उलझकर मुख्यमंत्रियों पर जितनी बातकरेगी वह सब व्यर्थ जाएगी। मुद्दा कोई गलत नहीं है। मगर समय सही नहीं है। यहऐसा

ही है जैसे इन सर्दियों में आप एसी कौन सा ज्यादा ठंडा करता है, इसकीबात करो। कोई नहीं सुनेगा। घर वाले भी नहीं। आप चाहे जितने बड़े एसीएक्सपर्ट बने रहो। मगर हीटर की बात करेंगे। तो भीड़ जुड़ने लगेगी। कश्मीर में एसी की बात करने वाले स्पेशलिस्ट से ज्यादा बात उस अर्द्ध ज्ञानी कीसुनी जाती है जो हीटर, कांगड़ी, बुखारी की बात करता है। दस साल हो गए लेकिन कांग्रेस अपनी कमियां खोजने में पूरी तरह असफल रही। और दससाल क्या कांग्रेस का पतन 2012 से शुरू हो गया था। इसलिए समीक्षा कालवहीं से रखना चाहिए। जब एक नकली आंदोलन ने कांग्रेस की सरकार और संगठनदोनों के हाथ पांव ढीले कर दिए थे। उस आंदोलन के लिए अन्ना, केजरीवाल या संघ को कोसने से क्या फायदा वे तो सफल थे। सरकार बदल दी। सवाल तो उनसेहोना चाहिए थे जो सरकार और संगठन में थे। उन्होंने क्या किया औरकांग्रेस ने कभी पूछा भी नहीं।

पी चिदंबरम गृह मंत्री थे। राहुल ने 7-8साल पहले कुछ पत्रकारों के साथ मुलाकात में जिसमें हम भी थे, कहा था किचिदम्बरम हमारे सबसे इन्टेलिजेन्ट नेताओं में हैं। वहीं चिदंबरम हाल में प्रणवमुखर्जी की राजनीति में असफल बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी की उस किताब केविमोचन में मौजूद थे जिसमें राहुल पर कटाक्ष और मजाक और सोनिया के खिलाफलिखी गई है। यहां यह भी याद दिला दें कि चिदंबरम जब तिहाड़ में थे तब सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह को लेकर उनसे मिलने गई थीं।

सो इन कांग्रेसियों का क्या इलाज है और क्या इनसे पार्टी को फायदा है।सोचने की बात यह है। कांग्रेसी अभी क्या कर रहे हैं नकल! सोशल मिडिया परजिस तर्ज पर मोदी पर लिखा जाता है उसी भाषा शैली में उनकी आलोचना। सोशलमीडिया के मुद्दों से राजनीति प्रभावित होगी या राजनीति अपने मुद्दों कोसोशल मीडिया, पब्लिक डिस्कोर्स में लाएगी कांग्रेस यह तक भूल गई।

भक्त कांग्रेस में भी हैं। और निसंदेह भाजपा के भक्तों से ज्यादा बेवकूफ। वेसत्ता में हैं। उस सत्ता का विरोध करने वालों का हौसला तोड़ने के लिएअटैक करते हैं। यहां तो केवल अर्थहीन गाली गलौज। किस के बारे में क्याबोल रहे हैं। कुछ नहीं मालूम। बस थोड़ा सा कुछ नया सा लिख दें। नेतृत्वहीन फौज की तरह जहां मन आए घुस जाओ। वहां तो एक पूरा आईटी सेल है।जो नियोजित है। कांग्रेस का सोशल मीडिया उसके सामने पूरी तरह फेल है।मगर उससे भी ज्यादा खराब बात यह है कि उसका लिखा अधकचरा नेता लोगराजनीतिक बयान में यूज कर रहे हैं। कांग्रेस की बौद्धिक क्षमता तो हमेशासे दक्षिणपंथियों के मुकाबले उच्च स्तर की रही है। मगर वह भी दोयम, औसत दर्जे के लोगों के हाथों में आ गई है। इसलिए वे वहां मोदी पर अटैककरते हैं जहां उन पर कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है। उन्हें मुख्यमंत्रीचुनने में आठ दिन हो जाएं, दस दिन हो जाएं जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता।किसे मुख्यमंत्री बनाया इससे भी नहीं। हर बात हर एक पर नहीं चिपकती है।

कांग्रेस के पास अभी एक कार्ड बचा हुआ है। खडगेजी की नई टीम अभी नहींबनी है। सही मौका है। सब नाकारा लोगों को निकाल कर बाहर करने का। नए औरकाम करने वाले लोगों को लाने का। राहुल, प्रियंका और खरगे याद रखें कि नएलोग उतना नुकसान नहीं करेंगे जितना पुराने कर चुके हैं। 2012 से अब तक।नए जो भी करेंगे कांग्रेस को फायदा ही होगा। इन्डिया गठबंधन उसकी बड़ी ताकत है। उसमें ध्यान लगाएं। प्रेसकान्फ्रेंस करने से कुछ नहीं होगा। कांग्रेसियों ने रिकार्ड प्रेसकान्फ्रेंसें की हैं। चुनाव के दौरान राज्य के नेताओं को दूसरे जरूरी कामछोड़कर दिल्ली से जाने वाले इन कांग्रेसियों की प्रेस कान्फ्रेंस केइंतजाम में जुटना होता था। सबको बढ़िया होटल, बड़ी कार और साथ में रहनेके लिए वरिष्ठ आदमी चाहिए होते थे। जाने कितने पदाधिकारी, आब्जर्वर,कोआर्डिनेटर इन तीन राज्यों में घूमते रहते थे। प्राइवेट जहाजों से। दोकौड़ी का काम नहीं और नुकसान मनों का! 2024 लोकसभा कांग्रेस के लिए आखिरी मौका है। मैच अभी भी गया नहीं है। हाथमें है। बेरोजगारी, महंगाई, सरकारी शिक्षा, चिकित्सा आज भी बड़े इश्यू हैं।अगर इन्हें लेकर एक सीट पर एक लड़ लिए तो मोदी जी के लिए बहुत मुश्किल होजाएगी। हिन्दू-मुसलमान कुछ नहीं चलेगा। बस सीट शेयरिंग इस भावना से होजाए कि हमारी कितनी सीटें आ रहीं है, यह मायने नहीं रखता उन्हें हराना है।

भाजपा को दक्षिण, कांग्रेस को उत्तर पर ध्यान देना चाहिए...

पांच राज्यों के चुनाव संपन्न होने के बाद सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। भाजपा इक्षहदी पट्टी में अपना गढ़ बनाए रखने को लेकर आश्वस्त है और विपक्ष उन्हें प्रभावी ढंग से चुनौती देने में विफल रहा है। भाजपा ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव जीते हैं। भाजपा भारत में एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति बन गई है। पार्टी ने अपनी पहुंच का विस्तार किया है और वर्तमान में 18 राज्यों में सत्ता पर काबिज है। यह इसके दृढ़ नेतृत्व, सुव्यवस्थित संरचना, विशाल संसाधनों और प्रभावी संचार के कारण है। इसके अलावा, भारतीय राजनीति में दक्षिणपंथ की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है। नरेंद्र मोदी और अन्य विपक्षी नेताओं की लोकप्रियता रेटिंग में काफी अंतर है। पार्टी का नया नारा है 'नई गति, नई प्रतिज्ञा।'

कल्याणी शंकर

पिछले दस वर्षों में मोदी ने भाजपा की हिंदू राष्ट्रवाद की मूल अवधारणा को प्रभावी ढंग से बढ़ावा दिया है। पार्टी ने मतदाताओं को जीतने के लिए नकद हस्तांतरण, मुफ्त राशन और किफायती गैस सिलैंडर जैसी कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं। एक और महत्वपूर्ण विचार, अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन अगले साल जनवरी में करने की योजना है। उच्च बेरोजगारी, मुद्रास्फीति और मूल्य वृद्धि जैसी चुनौतियों का सामना करने के बावजूद, ये योजनाएं जनता के बीच लोकप्रिय बनी हुई हैं। हालांकि, 2024 में लोग मोदी को तीसरा कार्यकाल देंगे या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को दक्षिणी राज्यों में चुनाव जीतने के लिए केवल मोदी के करिश्मे पर निर्भर रहने से परे नई रणनीतियां अपनानी होंगी। उन्हें पहले पार्टी के भीतर किसी भी आंतरिक असहमति का समाधान करना चाहिए।

दूसरे, उन्हें एक नया आख्यान तैयार करने की जरूरत है, जो दक्षिणी राज्यों के मतदाताओं के साथ प्रतिध्वनित हो। इक्षहदुत्व और सनातन धर्म की मौजूदा विचारधारा इन राज्यों के लोगों को पसंद नहीं आ रही, जो भाजपा को एक ऐसी पार्टी के रूप में देखते हैं, जो उत्तर भारत की जरूरतों को पूरा करती है। अन्य राजनीतिक दलों के विपरीत, द्रविड़ दलों ने दशकों से सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन द्रविड़ प्रशासन मॉडल के बारे में बात करते रहे हैं। दक्षिणी क्षेत्र में 543 लोकसभा सीटों में से 131 हैं। केरल में कई कम्युनिस्ट समर्थक हैं, तमिलनाडु मुख्य रूप से नास्तिक है और भाजपा का कर्नाटक में कुछ आधार है। हालांकि, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जिससे इन राज्यों में भाजपा का समर्थन सीमित है।

विपक्षी समूह 'इंडिया' हाल के चुनावों में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन से निराश है। अगर सबसे पुरानी पार्टी कम से कम दो उत्तरी भारतीय राज्यों में जीत हासिल करती तो राहुल गांधी सफल हो सकते थे। कांग्रेस को अगले चुनाव से पहले अपनी नई चुनावी रणनीति में सुधार करना होगा। मोदी को चुनौती देने के लिए अगले चार महीनों में गैर-भाजपा वोटों के विभाजन को रोकने के लिए विपक्षी दलों को एकजुट होना होगा। पहले कदम के रूप में, वे उन सीटों पर एक ही उम्मीदवार खड़ा करने पर सहमत हुए जहां भाजपा प्राथमिक दावेदार है। कांग्रेस पार्टी को सफलता की अधिक संभावना वाले निर्वाचन क्षेत्रों को जीतने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। व्यक्तिगत लाभ और अहंकार पर सत्तारूढ़ पार्टी को हराने को प्राथमिकता देना

आवश्यक है।

कांग्रेस को अपने नेतृत्व को अद्यतन करने और पुरानी प्रथाओं को पीछे छोड़ने की जरूरत है। तृणमूल कांग्रेस ने कांग्रेस के खराब प्रदर्शन की आलोचना की और कहा कि भाजपा की जीत कांग्रेस की विफलता का नतीजा है। आंतरिक संघर्षों, कमजोर गठबंधनों और वर्तमान राजनीतिक माहौल की समझ की कमी के कारण कांग्रेस चुनाव हार गई। सुधार के लिए, कांग्रेस को उचित भूमिकाओं के लिए सक्षम व्यक्तियों की भर्ती करनी और अपने समर्थकों को प्रेरित करना चाहिए।

राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी को पुनर्जीवित करने के लिए 4,000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व किया। इससे पार्टी को गुजरात और तेलंगाना में महत्वपूर्ण जीत हासिल करने में मदद मिली। हालांकि, यात्रा की गति मुख्यत: दक्षिण भारत तक ही सीमित थी और उत्तर में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

भाजपा से मुकाबला करने के लिए विपक्ष को अधिक धन की आवश्यकता है। भगवा पार्टी अपने फंड का इस्तेमाल अपने नेता को लोगों की नजरों में बनाए रखने के लिए करती है और उसे 2022-23 में 719 करोड़ रुपए मिलेंगे। कांग्रेस पार्टी का चंदा पिछले साल के 95.4 करोड़ रुपए से घटकर 79 करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस को 1,547.43 करोड़ रुपए की तुलना में भाजपा को 10,122.03 करोड़ रुपए मिले। कांग्रेस में कॉर्पोरेट योगदान कम हो गया है, जबकि भाजपा का योगदान बढ़ गया है। हालिया रिपोर्टों के अनुसार, कांग्रेस धन की कमी के कारण अपने चुनाव अभियानों को वित्तपोषित करने के लिए क्राऊड फंड्क्षडग पर विचार कर रही है। इसे भाजपा की युद्धक खजाने से मेल खाने के लिए विशाल धन की आवश्यकता है।

पिछले 20 वर्षों में, लोकसभा चुनावों पर खर्च छह गुना बढ़ गया है- 9,000 रुपए से लेकर भाजपा के 55,000 करोड़ तक। खर्च का एक तिहाई हिस्सा अभियान और प्रचार के लिए आबंटित किया जाता है। इसके विपरीत, दूसरा सबसे बड़ा खर्च मतदाताओं को सीधा भुगतान है। इसके अलावा, राजनीतिक दल अब मतदाताओं को नकद और वस्तु के रूप में रिश्वत देने का सहारा लेते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो भाजपा को दक्षिण के लिए विजयी रणनीति विकसित करने की जरूरत है, जबकि कांग्रेस को उत्तर पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जहां तक क्षेत्रीय दलों की बात है तो उनकी प्राथमिकता अपने वफादार मतदाता आधार को बनाए रखने की होनी चाहिए। इसके अलावा, मतदाताओं को जीतने के लिए केवल मुफ्त उपहार देना हमेशा पर्याप्त नहीं होता। उनका विश्वास और समर्थन अर्जित करने के लिए और अधिक प्रयास करना आवश्यक है। भारत की लोकतांत्रिक यात्रा एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जिसकी शायद ही कोई मिसाल हो। अपनी खामियों के बावजूद लोकतंत्र बचा हुआ है और सत्ता का हस्तांतरण 17 बार हो चुका है। आखिरकार, यह अरबों मतदाता ही हैं, जो भविष्य तय करेंगे।

EPFO sees surge in women subscriber in FY23

Retirement fund body EPFO recorded a net new women subscribers addition of 28,69,688 in FY23 against 15,93,614 in 2019-20, showing a rise in employment through the pandemic, Parliament was informed on Thursday. The net addition in Employees' Provident Fund Organization (EPFO) subscriptions is an indicator of the extent of job creation/formalisation of the job market and the coverage of social security benefits to the organised/ semi-organised sector workforce, said Minister of State for Labour & Employment Rameshwar Teli in a written reply to the Rajya Sabha.

Teli explained that the EPFO data covers the low-paid workers in medium and large establishments of the formal sector. According to the reply, the net addition in women EPFO subscribers increased from 15,93,614 in 2019-20 to 28,69,688 in 2022-23. The net women EPFO subscribers addition was 13,98,080 in 2020-21 and 26,18,728 in 2021-22. Teli also informed the House that the estimated female unemployment rate (UR) on usual status for persons of age 15 years and above in the country declined to 2.9 per cent in 2022-23 from 4.2 per cent in 2019-20, as per the Periodic Labour Force Survey (PLFS). It was 3.5 in 2020-21 and 3.3 in 2021-22.

The data indicates that the labour force indicators in 2022-23 for women are better than the pre-Covid period, the minister told the House. Teli said the estimated female worker population ratio (WPR) increased to 35.6 per cent during 2022-23 from 28.7 per cent in 2019-20, which shows that female employment in the country has an increasing trend. Employment generation, coupled with improving employability, is the priority of the government, Teli said, adding that the government has taken various steps to increase employability in the country, including women's participation in the labour force and quality of their employment. A number of protective provisions have been incorporated in the labour laws for equal opportunity and congenial work environment for women workers, he stated.

The Code on Social Security, 2020, has provisions for enhancement in paid maternity leave from 12 weeks to 26 weeks, provision for mandatory creche facility in establishments having 50 or more employees, permitting women workers in the night shifts with adequate safety measures, etc.

The Code on Occupational Safety, Health And Working Conditions (OSH), 2020, has provisions for the employment of women in aboveground mines, including opencast workings has been allowed between 7 pm and 6 am and in below-ground working between 6 am and 7 pm in technical, supervisory and managerial work, where continuous presence may not be required.

The Code on Wages 2019 has provisions that there shall be no discrimination in an establishment or any unit thereof among employees on the grounds of gender in matters relating to wages by the same employer in respect of the same work or work of a similar nature done by any employee.

Further, Teli stated that no employer shall make any discrimination on the grounds of sex while recruiting any employee for the same work or work of a similar nature in the conditions of employment, except where the employment of women in such work is prohibited or restricted by or under any law for the time being in force. To enhance the employability of female workers, the government is providing training to them through a network of Women's Industrial Training institutes, National Vocational Training Institutes and Regional Vocational Training Institutes.

राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा हेतु की गई संभागीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति

17 दिसंबर को आयोजित होगी राज्य सेवा व राज्य वन सेवा परीक्षा

इंदौर। मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा व राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 का आयोजन 17 दिसंबर को किया जा रहा है। यह परीक्षा दो सत्रों में प्रातः 10 बजे से 12 बजे एवं दोपहर 2ः15 बजे से 4ः15 बजे तक प्रदेश के 52 संभाग/जिला मुख्यालय में आयोजित की जाएगी। उक्त परीक्षा हेतु निर्धारित परीक्षा केन्द्रों के निरीक्षण कार्य के लिए आयोग द्वारा 14 संभागीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है। परीक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या के निराकरण हेतु संभागीय पर्यवेक्षकों से संपर्क किया जा सकेगा।

आयोग द्वारा उज्जैन संभाग हेतु सेवानिवृत्त आईएएस श्री एस.बी. सिंह (मोबाइल नम्बर 94251-30030),नर्मदापुरम संभाग हेतु सेवानिवृत्त आईएएस श्री शिवनारायण रूपला (मोबाइल नम्बर 94251-47740), ग्वालियर जिले के लिये सेवानिवृत्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री आनंद बिहारी गुप्ता (मोबाइल नम्बर 94251-09125), ग्वालियर संभाग हेतु सेवानिवृत्त उच्च न्यायिक सेवा श्री एन.सी. नागराज (मोबाइल नम्बर 97520-76098), भोपाल जिला हेतु सेवानिवृत्त आईएसएस श्री अशोक कुमार भार्गव (मोबाइल नम्बर 94254-27525), भोपाल संभाग हेतु सेवानिवृत्त आईएसएस श्री बी.आर. नायडू (मोबाइल नम्बर 94256-02333), सागर संभाग हेतु पूर्व सदस्य मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग डॉ. देवेन्द्र सिंह मरकाम (मोबाइल नम्बर 8827104693), शहडोल संभाग हेतु सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश श्री अनिल पारे (मोबाइल नम्बर 94250-66100), जबलपुर जिले के लिये पूर्व अध्यक्ष मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग डॉ. विपिन ब्यौहार (मोबाइल नम्बर 78699-17345), जबलपुर संभाग हेतु सेवानिवृत्त आईएएस श्री कृष्णमोहन गौतम (मोबाइल नम्बर 9425047345), रीवा संभाग हेतु सेवानिवृत्त आईएएस श्री राजकुमार पाठक (मोबाइल नम्बर 94254-13561), इंदौर जिले के लिये सेवानिवृत्त मुख्य वन संरक्षक श्री अशोक बरोनिया (मोबाइल नम्बर 94251-19940), इंदौर संभाग हेतु सेवानिवृत्त आईएसएस श्री महेन्द्र सिंह भिलाला (मोबाइल नम्बर 94250-93588) तथा चम्बल संभाग हेतु सेवानिवृत्त आईएएस श्री शेखर वर्मा (मोबाइल नम्बर 99265-81755) को सभागीय पर्यवेक्षक बनाया गया है।

इसके अतिरिक्त आयोग के सतर्कता अधिकारी उप पुलिस अधीक्षक प्रिया सिंह के मोबाइल नंबर 83059-73940 पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकेगी। आयोग द्वारा नियुक्त संभागीय पर्यवेक्षकों द्वारा परीक्षा तिथि के एक दिवस पूर्व परीक्षा केन्द्रों की व्यवस्था देखी जाएगी तथा आवश्यक सुधार हेतु सुझाव दिए जाएंगे। उनके द्वारा परीक्षा दिवस पर परीक्षा केन्द्रों का आकस्मिक निरीक्षण भी किया जाएगा एवं अभ्यर्थियों से प्राप्त शिकायतों के त्वरित निराकरण हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

18 लाख में खरीदी टाटा नेक्सॉन की कार, शोरूम से निकली कार की हालात खराब

नईदिल्ली, एजेंसी। घर और कार का सपना हर किसी का सपना होता है। नई चमचमाती कार के साथ अलग ही रुतबा झलकता है, लेकिन बेंगलुरु के रहने वाले शरथ कुमार के साथ नई कार का अनुभव अलग ही रहा। शरथ कुमार ने 18.2 लाख रुपये में नई टाटा नेक्सॉन कार खरीदी थी। दोस्तों के साथ कार की डिलीवरी लेने के लिए प्रेरणा मोटर्स नाम के शोरुम पहुंचे। ब्रांड न्यू कार के जब पर्दा हटा तो शरथ के होश उड़ गए। लाखों की कार में ढेर सारी खामियां थी।

नई कार में खामियां: शरत जब कार की डिलीवरी लेने शोरूम पहुंचे, उन्हें कार की चाबी थमा दी गई। कार से पर्दा हटाया गया। कार को देखखर शरथ हैरान रह गए। नेक्सॉन फेसलिफ्ट ऑटोमैटिक पेट्रोल फियरलेस प्लस में कई खामियां थी। नई कार में पानी से भरी हेडलाइट्स, फ्रंट बम्पर पर खरोंच, क्वार्टर पैनल फ्रेम और टेलगेट फ्रेम के साथ-साथ घटिया वेल्डिंग लगे थे। गलत तरीके से फिट किए गए डोर रबर बीडिंग लगाए गए थे। टेगेट फ्रेम पर कई स्क्रैच आए हुए थे। दरवाजे की वेल्डिंग काफी कमजोर थी। नई कार में इतनी सारी कमियों को देखकर शरथ दंग

रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि इस कार के लिए उन्होंने 18 लाख रुपये चुकाए हैं।

उन्होंने अपना ये एक्सपीरियंस सोशल मीडिया पर शेयर किया। उन्होंने लिखा कि शोरूम ने उन्हें खराब टाटा नेक्सॉन कार थमाने की कोशिश की। उन्होंने त्त्ष्ट में मेरे नाम पर वाहन का रजिस्ट्रेशन कर दिया। उन्होंने टाटा मोटर्स से इसकी कई बार शिकायत की, कार की खामियों को उनतक पहुंचाया, लेकिन कंपनी की प्रतिक्रिया निराशाजनक रही। कंपनी और शोरूम दोनों ने न तो उनकी कार बदली और न ही उन खामियों को दूर किया। एक महीना बीत जाने के बावजूद कंपनी की ओर से कोई एक्शन नहीं लिया गया। कंपनी ने उनकी शिकायत को दूर करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। कंपनी की ओर से उन्हें 2 साल की वारंटी के साथ असी कार को स्वीकार करने पर जोर दिया जा रहा है। शरथ ने कहा है कि वो टाटा मोटर्स की ओर से उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है। कंपनी को उन्होंने पूरी जानकारी दी है, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब शरथ कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है।

संभागायुक्त माल सिंह ने किया अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज और छात्रावासों का औचक निरीक्षण

इंदौर। इंदौर संभागायुक्त माल सिंह ने गत दिवस खंडवा रोड मोरोड़ में ज्ञानोदय छात्रावास, एकलव्य छात्रावास और गुरुकुल छात्रावास का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने उक्त छात्रावासों में छात्रों को उपलब्ध सुविधाएं, भोजन, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, साफ सफाई आदि की जानकारी लेते हुए व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने छात्रावास में रह रहे छात्रों से बातचीत कर फीडबैक लेते हुए छात्रावास में उपलब्ध सुविधाओं में किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं है इसकी भी जानकारी ली। उन्होंने भोजन कक्ष एवं रसोई कक्ष का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि छात्रावास में निवासरत बच्चों के शारीरिक व मानसिक विकास के लिए मार्गदर्शक गतिविधियां निरंतर रूप से आयोजित कराई जाएं। वहीं बुधवार को संभागायुक्त ने अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज का भी आकस्मिक निरीक्षण किया और वहां मौजूद उपकरणों की कार्यशील स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने चिकित्सालय के भवन में किए जाने वाले मरम्मत कार्य को शीघ्र संपन्न करने के दिशा-निर्देश दिए। साथ ही पूर्व भ्रमण के दौरान दिये गये निर्देशों की पालन स्थिति की जानकारी भी ली।

आईपीओ से कंपनियों को बंपर फायदा, एसेंट माइक्रोसेल का लक्ष्य सिर्फ 78 करोड़ लेकिन मिले 18,900 करोड़

नईदिल्ली, एजेंसी। मुख्य प्लेटफॉर्म पर आईपीओ लाकर रिकॉर्ड बना रहीं कंपनियों की तरह ही छोटी और मझोली कंपनियां (एसएमई) भी रिकॉर्ड बना रही हैं। पहली बार किसी एसएमई कंपनी के आईपीओ को रिकॉर्ड 18,900 करोड़ रुपये के लिए आवेदन मिला है। जबकि कंपनी को केवल 78 करोड़ रुपये जुटाने थे। मंगलवार को बंद हुए एसेंट माइक्रोसेल के इश्यू को 362 गुना का सब्सक्रिप्शन मिला है।

एसेंट माइक्रोसेल का शेयर ग्रे मार्केट में 300 रुपये से ज्यादा भाव पर कारोबार कर रहा है। आईपीओ में मूल्य 140 रुपये था। एसेंट माइक्रोसेल से पहले बेसिलिक फ्लाई स्टूडियो को 14,000 करोड़ रुपये के लिए आवेदन मिला था। इसमें 8,197 करोड़ रुपये तो खुदरा निवेशकों के थे। इससे पहले ओरियाना पावर को 60 करोड़ के एवज में 7,000 करोड़ रुपये का आवेदन मिला था। इसका शेयर 118 रुपये की तुलना में 302 रुपये पर सूचीबद्ध हुआ था। कृष्का स्ट्रैपिंग को 4,391 करोड़ रुपये के लिए आवेदन मिले थे।

इस साल लाभ देने में ये रहे अव्वल: इस महीने 8 इश्यू खुले हैं। इस साल अब तक कुल 169 आईपीओ आए हैं। इसमें से 121 ने लिस्टिंग पर फायदा दिया है। इन्होंने रिकॉर्ड 4,000 करोड़ से ज्यादा जुटाए हैं। 2022 में 109 कंपनियों ने 1,980 करोड़, 2021 में 59 कंपनियों ने 787 करोड़, 2020 में 27 कंपनियों ने 168 करोड़ जुटाए थे।

730 गुना तक मिला सब्सक्रिप्शन: काहां पैकेजिंग का इश्यू सबसे ज्यादा 730 गुना इस साल भरा था। नेट अवेन्यू 511 गुना, मैत्रेय मेडिकेयर 446 गुना भरा था। मधुसूदन मसाला को 444 गुना, एनलॉन टेक को 428 गुना और दपिक केटेक्स के इश्यू को 403 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था।

ओपीएस से राज्यों पर बढ़ेगा दबाव, बाधित होगी विकास कार्य की क्षमता, आरबीआई ने की टिप्पणी

नईदिल्ली, एजेंसी। आरबीआई ने आगाह करते हुए कहा है कि महंगाई भत्ते (डीए) से जुड़ी पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को लागू करने से राज्यों के खजाने पर काफी दबाव बढ़ेगा। इससे उनकी विकास कार्यों पर खर्च करने की क्षमता प्रभावित होगी। केंद्रीय बैंक ने 'राज्यों के वित्त : 2023-24 के बजट का एक अध्ययन' विषय पर जारी रिपोर्ट में कहा, समाज एवं उपभोक्ता के लिहाज से अहितकर वस्तुओं व सेवाओं, सब्सिडी और हस्तांतरण व गारंटी पर प्रावधान से राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति गंभीर स्थिति में पहुंच जाएगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने और कुछ अन्य राज्यों के भी इसी दिशा में आगे बढ़ने से आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिहाज से खर्च करने की प्रदेश सरकारों की क्षमता सीमित हो जाएगी।

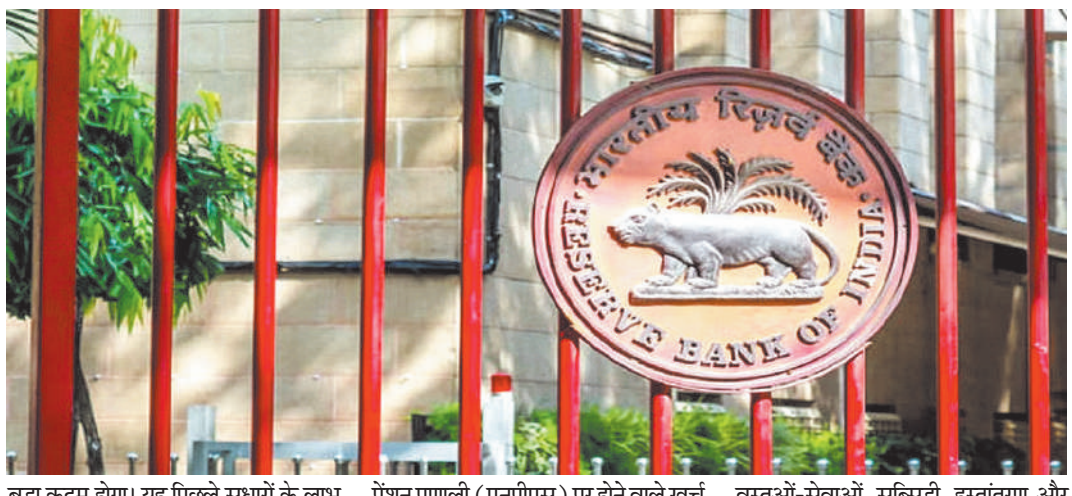

बड़ी चिंता: पुरानी पेंशन व्यवस्था को अपनाना राज्यों के लिएपीछे जाने की दिशा में

बड़ा कदम होगा। यह पिछले सुधारों के लाभ को कम करेगा व आने वाली पीढ़ियों के हितों से समझौता करेगा।

अगर सभी राज्य ओपीएस व्यवस्था को अपनाते हैं तो कुल राजकोषीय बोझ राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) पर होने वाले खर्च का 4.5 गुना तक अधिक हो सकता है। अतिरिक्त बोझ 2060 तक सालाना जीडीपी के 0.9 फीसदी तक पहुंच जाएगा।

समाज के नजरिये से अहितकर वस्तुओं-सेवाओं, सब्सिडी, हस्तांतरण और गारंटी के लिए अतिरिक्त प्रावधान राज्यों की वित्तीय स्थिति को गंभीर बना देगा। इससे दो वर्षों में हासिल समग्र राजकोषीय मजबूती बाधित होगी।

खजाने पर ऐसे बढ़ेगा बोझ: इससे पुरानी पेंशन व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले सेवानिवृत्त लोगों के लिए पेंशन का बोझ बढ़ेगा। इन लोगों का अंतिम बैच 2040 के दशक की शुरुआत में सेवानिवृत्त हो सकता है। इसलिए, वे 2060 के दशक तक ओपीएस के तहत पेंशन प्राप्त करेंगे।

राज्यों पर कर्ज अखिल भारतीय स्तर से ज्यादा: रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ राज्यों ने 2023-24 में राजकोषीय घाटे को जीएसडीपी (राज्य सकल घरेलू उत्पाद) के चार फीसदी से अधिक करने का बजट रखा है, जबकि अखिल भारतीय औसत 3.1 फीसदी है। उनका कर्ज स्तर भी जीएसडीपी के 35 फीसदी से अधिक है। अखिल भारतीय औसत 27.6 प्रतिशत है।

राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब व हिमाचल प्रदेश ने अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने के फैसले की जानकारी दी है।

आम आदमी को महंगाई का झटका! सीएनजी की कीमतों में हुआ इजाफा

नईदिल्ली, एजेंसी। आम आदमी को आज सुबह महंगाई का बड़ा झटका लगा है। तीप हफ्ते में दूसरी बार सीएनजी की कीमतों में इजाफा हो गया है। राजधानी दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी हो गई है। इन शहरों में सीएनजी की कीमतों में एक रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी की गई है। नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में सीएनजी के रेट 76.59 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गए हैं। वहीं नोएडा में सीएनजी के नए दाम 82.20 रुपये प्रति किलो और ग्रेटर नोएडा में 81.20 रुपये प्रति किलो पर आ गए हैं।

नवंबर में बढ़े थे दाम: दिल्ली-एनसीआर में इससे पहले बीते 23 नवंबर को सीएनजी की कीमतों में एक रुपये प्रति किलोग्राम का इजाफा किया गया था। इसके बाद दिल्ली में सीएनजी की कीमत 74.59 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 75.59 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई थी। वहीं नोएडा में सीएनजी के दाम 80.20 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 81.20 रुपये प्रति किलोग्राम हो गए थे।

मानकों में किया था बदलाव: इससे पहले केंद्र सरकार ने जुलाई में सीएनजी की कीमत तय करने के मानकों में बदलाव किया था। इसके बाद दिल्ली सहित कई राज्यों में सीएनजी की कीमत में बड़ी गिरावट दर्ज की गई थी। लेकिन आईजीएल ने अगस्त में कीमतों में इजाफा कर दिया था। यह एक साल में दूसरी बार भाव में बढ़ोतरी थी। दिल्ली-एनसीआर में 23 अगस्त को भी सीएनजी की कीमत एक रुपये बढ़ी थी।

भारत में निवेश के अपार अवसरः गोयल

नईदिल्ली, एजेंसी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को कहा कि विदेशी निवेशकों को भारत में कारोबार के अवसर तलाशने चाहिए।

उन्होंने कहा कि भारत एक बड़ा घरेलू बाजार है और यहां निवेश के अनुकूल माहौल है। मंत्री ने कहा कि कुशल श्रम की उपलब्धता, सभी निवेशकों के साथ समान व्यवहार और आकांक्षी युवा आबादी के चलते यहां निवेश करना लाभप्रद है। उन्होंने एक निवेश सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, ''भारत में निवेश के अवसर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और निवेश पर अच्छा प्रतिफल मिल रहा है। मैं आपको पूर्वोत्तर राज्यों तथा जम्मू-कश्मीर में संभावनाएं तलाशने के लिए भी आमंत्रित करता हूं। उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद निर्यात भी बढ़ रहा है।

अमेरिका के केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरों में नहीं किया कोई बदलाव, दुनियाभर के शेयर बाजारों को मिली राहत

नईदिल्ली, एजेंसी। अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। बता दें कि अमेरिका में ब्याज दरें 22 साल के अधिकतम स्तर पर हैं। हालांकि केंद्रीय बैंक के बैंकरों ने संकेत दिए हैं कि अगले साल इनमें कटौती हो सकती है। यह दुनियाभर के शेयर बाजारों के लिए राहत की बात है। फेडरल रिजर्व ने बुधवार को ब्याज दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं करने का एलान किया। उल्लेखनीय है कि फेडरल रिजर्व ने बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए मार्च 2022 से 11 बार ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। जिसके चलते अमेरिका में ब्याज दर बीती गर्मियों में चार दशकों के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी।

अमेरिका के आवास बाजार को राहत मिलने की उम्मीद: फेडरल रिजर्व ने अनुमान जताया है कि अगले साल यानी 2024 में पूर्वानुमानों से भी ज्यादा ब्याज दरों में कटौती की जा सकती है। यह कटौती तीन तिमाही अंक तक हो सकती है। इससे उच्च बंधक दरों के चलते कमजोर मांग का सामना कर रहे अमेरिका के आवास बाजार को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। फेडरल रिजर्व का कहना है कि महंगाई पिछले साल के मुकाबले कम हुई है लेकिन यह अभी भी उच्च स्तर पर है। फेडरल रिजर्व की मॉनेटरी पॉलिसी निर्धारित करने वाले अधिकारियों का पैनल द फेडरल ओपन मार्केट कमेटी ने ब्याज दरों को 5.25-5.50 के बीच रखा है।

फैसले के बाद अमेरिकी शेयर बाजार में देखा गया उछाल: फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों में बढ़ोतरी ना करने के फैसले के बाद अमेरिकी स्टॉक मार्केट के प्रमुख इंडेक्स डाउ जोंस इंडस्ट्रियल एवरेज में 200 अंकों का उछाल देखा गया। अमेरिका के केंद्रीय बैंक ने 2024 में अपना महंगाई का पूर्वानुमान भी घटाकर 2.6 फीसदी से 2.4 फीसदी कर दिया है। फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉवेल ने स्वीकार किया कि महंगाई कम करने के केंद्रीय बैंक के प्रयासों का असर दिखना शुरू हो गया है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अभी लंबा रास्ता तय करना है। उम्मीद जताई जा रही है कि फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों में कटौती का दौर अगले साल जून में शुरू हो सकता है और 0.25 प्रतिशत की कटौती तीन बार करके कुल 0.75 प्रतिशत की कटौती की जा सकती है।

जितनी आपकी सैलेरी है, उतने का चॉकलेट खरीद कर खा लेते हैं अमीरजादे

नईदिल्ली, एजेंसी। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले मध्यमवर्गीय या निम्न मध्यमवर्गीय लोगों की हालत चक्की के दो पाटों के बीच पिसने वाले अनाज की भांति हो गई है। एक ओर दफ्तर में उनकी सैलेरी में पर्याप्त इजाफा नहीं हो रहा है। छंटनी की तलवार लटकती ही रहती है। दूसरी तरफ खाने-पीने की चीजें महंगी होती जा रही हैं। ऊपर से दिखावा अलग से जान मार रहा है। स्थिति यह हो गई है कि भारतीय 13 हजार रुपये से 65,000 रुपये प्रति बॉक्स के रेट पर बिकने वाले इंपोर्टेड चॉकलेट धड़ल्ले से खरीद रहे हैं। प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले अधिकतर मजदूरों की महीने की सैलेरी भी इतनी ही होती है।

तेजी से बढ़ रही है प्रीमियम इंपोर्टेड चॉकलेट की मांग: ईटी में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक इन दिनों लक्जरी और प्रीमियम इंपोर्टेड चॉकलेट की मांग तेजी से बढ़ रही है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत ने 27.84 मिलियन डॉलर मूल्य की चॉकलेट का इंपोर्ट किया है। यह आंकड़ा साल-दर-साल 45 प्रतिशत की ग्रोथ दर्शाता है। इनमें से अधिकतर बेल्जियम और यूके जैसे देशों से आते हैं।

इतने महंगे हैं प्रीमियम चॉकलेट: भारत में इंपोर्टेड चॉकलेट के वितरक कोकोकार्ट के को-फाउंडर करण आहूजा का कहना है कि

कंपनियों की आधी बिक्री प्रीमियम चॉकलेट कैटिगरी से हुई थी। कुछ लोगों द्वारा डार्क चॉकलेट को सुपरफूड मानने के कारण, कुछ वर्षों में बाजार पहचान से परे हो जाएगा।

उन्होंने बताया कि कंपनी ने 2022 में इतालवी ब्रांड वेंची लॉन्च किया, जिसका कोकोकार्ट में सबसे महंगा उत्पाद उनका 54-पीस चॉकलेट सिगार बॉक्स है, जिसमें पांच किलोग्राम मिक्स्ड चॉकलेट सिगार की कीमत 64,995 रुपये है। कोकोकार्ट 2024 में बटलर, लियोनिडास, गुइलियन और कार्टराईट एंड बटलर जैसे ब्रैंड पेश करने पर भी विचार कर रहा है, जो बेल्जियम और यूके से इंपोर्ट किए जाते हैं।

कुछ और प्रीमियम ब्रांड भारत आने वाले हैं: सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि आने वाले दिनों में और अधिक आयातित प्रीमियम ब्रैंड भारत में प्रवेश करने की योजना बना रहे हैं।

भारत में स्विस लग्जरी चॉकलेट ब्रैंड स्त्रद्गह्लड्डष्द्ध (लेडेराच) की प्रवक्ता संस्कृति गुप्ता ने ईटी को बताया कि स्विस चॉकलेट ब्रैंड जो भारत में अपनी शुरुआत के बाद महत्वपूर्ण लोकप्रियता हासिल कर चुका है, डीएस समूह के साथ साझेदारी में महत्वपूर्ण भारतीय बाजारों में प्रवेश करने की योजना बना रहा है। लेडेराच की 64 ग्राम टैबलेट के लिए 1,050 रुपये से लेकर प्रालिन्स और ट्रफल्स के 72-पीस बॉक्स के लिए 16,700 रुपये तक कीमत है।

अमीरजादे किस तरह के चॉकलेट पसंद करते हैं: चॉकलेट इंडस्ट्री के इनसाइडर का कहना है कि भारत में लक्जरी और प्रीमियम चॉकलेट पसंद करने वाले आर्गेनिक प्रोडक्ट खोजते हैं। लोग डार्क चॉकलेट खूब खोजते हैं। इसके अलावा वीगन ग्लूटेन फ्री और सुगर फ्री चॉकलेट की भी खूब मांग निकल रही है।

चॉकलेट की बढ़ रही है स्वीकार्यता: वैसे भी पिछले कुछ सालों से समाज में चॉकलेट की स्वीकार्यता बढ़ी है। जिस तरह से मिलावटी मिठाई की खबरें फैल रही है, उसे देखते हुए लोग त्योहारों या मांगलिक अवसरों पर भी चॉकलेट के डिब्बे भेंट करने लगे हैं। अपने ही घर के बच्चों को एक तरफ लड्डू और दूसरी तरफ चॉकलेट का डिब्बा दिखाएं तो वह लड्डू को छोड़ चॉकलेट का डिब्बा लेने को दौड़ेगा।

गैर संक्रामक रोगों से मुकाबले के लिए हर्बल दवाएं बेहतर

गैर संक्रामक रोगों से मुकाबले के लिए हर्बल दवाएं काफी बेहतर हैं। हृदयरोग, कैंसर, स्ट्रोक इत्यादि गैर संक्रामक रोग (एनसीडी) के उपचार में इनका इस्तेमाल प्रभावी हो सकता है। सोसायटी फॉर एथनोफामोर्कोलॉजी, केंद्रीय आयुष मंत्रालय और बॉयोटेक्रोलॉजी विभाग के संयुक्त सम्मेलन में भारत और दुनिया के विभिन्न देशों के विशेषज्ञों ने खास तौर पर गैर संक्रामक रोगों का मुकाबला करने में जड़ी-बूटियों पर आधारित दवाओं की भूमिका पर जोर दिया।

इस सम्मेलन में 40 देशों के 60 से अधिक विशेषज्ञों ने सहभागिता की। कनाडा के टोरंटो से आए डॉ.प्रदीप विसेन ने मधुमेह के टाइप-2 और कार्डियो वस्कुलर रोगों के संबंध में औषधीय पादपों की उपयोगिता पर प्रकाश डाला। हृदय रोग, कैंसर और मधुमेह जैसे रोगों को पहले जहां सिर्फ संपन्न लोगों से जोड़ा जाता था, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) के मुताबिक अब ये वैश्विक खतरा बन चुके हैं और गरीब इनसे सबसे ज्यादा पीड़ित हो रहे हैं। एमिल फार्मा ने मधुमेह से लड़ने में बीजीआर-34 दवा की भूमिका के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि औषधीय पादपों से बनी यह दवा न सिर्फ नियमित रूप से रक्त में सर्करा की मात्रा को नियंत्रित करती है, बल्कि साथ ही हमारे मेटाबोलिज्म को भी नियंत्रित रखती है।

बांग्लादेश के ढाका विश्वविद्यालय के औषध निर्माण विज्ञान विभाग ने अपने प्रजेंटेशन में कहा कि आधुनिक चिकित्सा पद्धति की बहुत सी दवाओं को इन रोगों में प्रभावी माना गया है, लेकिन इनमें कैंसर कारक तत्व होते हैं और ये लीवर को गंभीर क्षति पहुंचाती हैं। उनके अध्ययन में जड़ी-बूटियों में पाए गए प्राकृतिक तत्वों की प्रभावशीलता को रेखांकित किया है। इनके अलावा नाइजीरिया की टेक्सोकोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ अबुजा ने कार्डियोवस्कुलर रोगों में पादपों के औषधीय महत्व पर चर्चा की। उन्होंने इसका अध्ययन जानवरों पर भी किया है। ऑस्ट्रेलिया में त्रिगोनेला लैब्स के निदेशक डॉ.दिलिप घोष ने मधुमेह के प्रबंधन में फेनुग्रीक बीज की भूमिका पर चर्चा की, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका में जीआरएएस (सामान्य तौर पर सुरक्षित) का दर्जा दिया।

डायबिटीज की यह दवाई बना सकती है आपको दिल का मरीज

डायबिटीज से पीड़ित लोगों को कई तरह की सावधानियां बरतने के साथ ही इसे नियंत्रित रखने के लिए दवाइयों का सेवन भी करना पड़ता है.ऐसी ही दवाइयों में से एक है रोसिग्लिटाजोन, जो कि डायबिटीज टाइप-2 के मरीज खाते हैं.यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) ने 1999 में इस दवा को अवांदिया ड्रग्स के नाम से मंजूरी दी थी.अभी हाल में हुए एक रिसर्च में यह बात सामने आयी है कि यह दवा खाने से दिल की बीमारी 33 प्रतिशत तक अधिक बढ़ सकती है. मेडिकल न्यूज टुडे की खबर के अनुसार, इसके दुष्प्रभावों को देखते हुए यूरोप में इस दवा के इस्तेमाल पर सख्त मनाही है.गौरतलब है कि अपने देश में इस दवा की बिक्री होती है.रिपोर्ट के अनुसार, न्यू हैवन के येल स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के जोशुआ डी वालेक के मुताबिक, दूसरों की तुलना में अवांदिया दवा खाने वाले लोगों में दिल से संबंधित बीमारी होने का खतरा 33 प्रतिशत ज्यादा हो जाता है.

भविष्य में स्ट्रोक का कारण बनती है खराब जीवनशैली

खराब जीवनशैली की आदतों में तनाव, धूम्रपान, शराब का अत्यधिक सेवन, जंक फूड का सेवन और शारीरिक गतिविधि में कमी आदि शामिल हैं, जो भविष्य में स्ट्रोक का कारण बनती हैं, जबकि एक हेल्दी डाइट स्ट्रोक के 80 प्रतिशत मामलों को रोकने में मदद करती है. हेल्दी डाइट न केवल स्ट्रोक के जोखिम कारकों को कम करने में मदद करती है, बल्कि समग्र स्वास्थ्य को भी सही रखने में मदद करती है.स्ट्रोक के जोखिम को बढ़ाने वाले कारकों में उच्च रक्तचाप, डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल का उच्च स्तर शामिल हैं, जो हेल्दी डाइट की मदद से संतुलित रखे जा सकते हैं.

सैंडविच का सेवन करना चाहिए.बस ध्यान रखें कि उसमें अंडे का पीला हिस्सा नहीं होना चाहिए.

शराब का सेवन करने से बचें

शराब ब्रेन हेमरेज का खतरा बढ़ाता है.शराब से रक्तचाप का स्तर भी बढ़ता है, जिससे धमनी की अंदरूनी दीवार को नुकसान पहुंचता है.इसका यह मतलब है कि मस्तिष्क में खून का प्रवाह कम हो जाता है.शराब के अधिक सेवन से हृदय को भी नुकसान पहुंचता है, जिससे धड़कनों में गड़बड़ी की समस्या होती है.इसके परिणामस्वरूप, हृदय में थक्के बन सकते हैं, जिससे मस्तिष्क में खून का प्रवाह कम हो सकता है.

धूम्रपान करना बंद करें

स्ट्रोक निकोटिन से नहीं, बल्कि धुएं से होता है.आपको जान कर आश्चर्य होगा कि धूम्रपान स्ट्रोक के खतरे को तीन गुना बढ़ा देता है, इसलिए इसका सेवन बंद करना आवश्यक है.जब आप धूम्रपान करते हैं, आप धुएं को अंदर लेते हैं, जिसमें 7000 से ज्यादा जहरीले केमिकल मिले होते हैं.ये केमिकल आपके फेफड़ों से गुजरते हुए आपके पूरे शरीर के खून में मिल जाते हैं, जो शरीर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाती हैं.

4 से 5 घंटे के अंदर स्ट्रोक का उपचार संभव

स्ट्रोक का उपचार के लिए यह जानना सबसे जरूरी है कि स्ट्रोक किस प्रकार का है व इससे मस्तिष्क का कौन-सा भाग प्रभावित हुआ है.इसके अलावा जल्दी-से-जल्दी मरीज को अस्पताल ले जाने की जरूरत होती है. स्ट्रोक के द्वारा जो नुकसान होता है, उसे रोकने के लिए क्लॉट बस्टिंग ड्रग्स के पास 4 से 5 घंटे से कम का समय होता है.जिन मरीजों के मस्तिष्क की बड़ी धमनियां ब्लॉक हो गयी हैं, उनके लिए मेकैनिकल थ्रॉम्बेक्टोमी की सलाह सबसे अधिक दी जाती है.ब्लॉक हुई धमनियों को खोलने के लिए, डॉक्टर मूल क्षेत्र की धमनी से मस्तिष्क के प्रभावित क्षेत्र के लिए एक केथेटर डालते हैं. स्टेंट खुलता है और क्लॉट को जकड़ लेता है, डॉक्टर उस स्टेंट को क्लॉट सहित बाहर निकाल लेते हैं. इसके लिए खास सक्शन ट्यूब का भी प्रयोग होता है.यह प्रक्रिया स्ट्रोक के गंभीर लक्षणों के 6 घंटे के अंदर की जानी चाहिए. 80 प्रतिशत से अधिक मरीजों में ब्लॉकेज को खोल दिया जाता है और धमनियों में प्रवाह को पुन : स्थापित कर दिया जाता है. इससे लगभग 60 प्रतिशत मरीजों की हालत में तेजी से सुधार आता है.

उच्च रक्तचाप को रोकने के लिए डाइट

विशेष आहार या पोषक तत्वों के सेवन की लिमिट को तय करने से कोई फायदा नहीं है. ऐसी कई डाइट गाइडलाइंस हैं, जो पूरे डाइट पैटर्न के पालन की सलाह देती हैं. इन गाइडलाइंस के अनुसार, मीट का सेवन कम-से-कम करना चाहिए और ताजा फल व सब्जियों का अधिक-से-अधिक सेवन करना चाहिए.सब्जियां, फल और कम वसा वाले डेयरी फूड (दूध, दही आदि) के साथ कम फैट वाला आहार उच्च रक्तचाप के स्तर को कम करने में मदद करता है. अपने खाने में मछली, गेहूं, नट्स और पोल्ट्री को शामिल करें और रेड मीट, मिठाई और चीनी वाले जूस या कोल्ड ड्रिंक आदि का सेवन कम कर दें.यह डाइट प्लान सही पोषण की मदद से रक्तचाप को संतुलित बनाये रखने में मदद करता है.यदि उच्च रक्तचाप को केवल हेल्दी डाइट और मेडिकेशन से रोका जा सकता है, तो स्ट्रोक के 90 प्रतिशत मामलों को भी रोका जा सकता है.

शाकाहारी आहार को अपनाने की जरूरत इस तरह के आहार में फैट कम नहीं होता है, लेकिन यह कम ग्लाइसेमिक वाला आहार होता है, जिसमें मात्र 40 प्रतिशत कैलोरी होती है. इससे केवल लाभकारी वसा मिलती है जैसे- जैतून व कनोला तेल से मिलने वाली वसा शरीर के लिए फायदेमंद होती है.इसके अलावा कैलोरी गेहूं, फल, सब्जियां और फलियां आदि से मिलती है.डायबिटीज और उच्च रक्तचाप वाले मरीजों में स्ट्रोक होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है.डायबिटीज रक्त वाहिकाओं और नसों को नुकसान पहुंचा सकती हैं, जो स्ट्रोक का कारण बनती है. विभिन्न अध्ययनों के अनुसार, दालचीनी, मेथी के बीज, हल्दी की चाय, जीरा, लहसुन, इलायची, सौंफ, अदरक, आंवला, पालक, लौकी, फाइबर युक्त आहार, बादाम, करेला आदि चीजों को अपनी डाइट में शामिल करने से स्ट्रोक के खतरे में 47 प्रतिशत कमी लायी जा सकती है.रिपोर्ट्स के अनुसार, कोलेस्ट्रॉल का सेवन कम-से-कम किया जाना चाहिए.मछली या चिकन की तुलना में रेड मीट में फैट चार गुना ज्यादा होता है, जो स्ट्रोक के खतरे को अधिक बढ़ाता है.

कैसी डाइट का पालन करें

जिन मरीजों में स्ट्रोक की आशंका अधिक है, उन्हें मीट, रेड मीट और अंडे के पीले हिस्से के सेवन से बचना चाहिए.उन्हें लाभकारी तेल जैसे- जैतून और कनोला के तेल, गेहूं, सब्जियां, फलों और फलियों को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए.अंडे का सफेद हिस्सा प्रोटीन का अच्छा स्रोत होता है, इसलिए ऑमलेट और अंडे व सलाद से बने

शुरुआती लक्षण और संकेत

- देखने में अचानक दिक्कत होना
- चक्कर आना
- चलने में अचानक तकलीफ
- बोलने में दिक्कत
- चेहरे में अचानक संवेदनशून्यता का आभास
- तेज सिरदर्द
- अचानक भ्रम की स्थिति व समझने में दिक्कत
- बांह में अचानक संवेदन शून्यता या कमजोरी

नोट : आमतौर पर सबाराकनॉइड हेमरेज में बिना वजह अचानक भयंकर सिरदर्द होने लगता है.इसके साथ ही उल्टी, दौरा या मानसिक चेतना का अभाव जैसी शिकायतें भी होती हैं.इन मामलों में नॉन-कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन तत्काल करा लेना चाहिए.

योग व ध्यान से होता है तेज दिमाग

योगियों के ध्यान व योग से दिमाग तेज होने वाले दावे की पुष्टि हुई है। एक नए शोध में यह सामने आया है कि ध्यान व श्वास से जुड़े व्यायाम जैसे प्राणायाम दिमाग को मजबूत बनाने व कार्यो पर ध्यान केंद्रित करने में मददगार साबित होता है। डबलिन के त्रिनिटी कॉलेज के शोध के प्रमुख खोजकर्ता इयॉन रॉबर्टसन ने कहा, 'हमारा शोध बताता है कि श्वास केंद्रित व्यायाम व दिमाग की स्थिरता के बीच मजबूत संबंध है।' इस शोध के निष्कर्षो का प्रकाशन पत्रिका 'साइकोफिजियोलॉजी' में किया गया है। इसमें श्वसन व ध्यान के बीच न्यूरोफिजियोलॉजिकल संबंध को बताया गया है। शोध से पता चलता है कि सांस लेना ध्यान का एक प्रमुख तत्व व दिमागी व्यायाम है। यह सीधे तौर पर दिमाग में प्राकृतिक रासायनिक संदेशवाहक के स्तर को प्रभावित करता है, जिसे नॉरएड्रीलीन कहते हैं। यह रासायनिक संदेशवाहक हमारे चुनौती, उत्सुकता, व्यायाम, ध्यान केंद्रित या भावनात्मक रूप से उत्तेजित होने पर जारी होते हैं, यदि यह सही स्तर पर उत्पन्न होते हैं तो यह दिमाग को नए संपर्क बनाने में मदद करते हैं। यह दिमाग के लिए टॉनिक के तौर पर काम करता है।

डिप्रेशन-एसिडिटी से दूर रखता है टमाटर

टमाटर का स्वाद थोडा खट्टा थोडा मीठा। टमाटर हर सब्जी को स्वादिष्ट और जायकेदार बनाता है, यह तो सब जानते हैं लेकिन एक नए अध्ययन में इसके एक अन्य गुण का पता चला है कि यह अवसाद से दूर रखने में सहायक है। टमाटर में भरपूर मात्रा में विटामिन सी, कैल्शियम, फास्फोरस पाये जाते हैं। एसिडिटी की शिकायत होने पर टमाटरों की खुराक बढाने से यह शिकायत दूर हो जाती है।

अनुसंधानकर्ताओं ने इसके लिए 70 अथवा उससे अधिक उम्र के करीब 1000 पुरूष और महिलाओं के भोजन की आदत और उनके मानसिक स्वास्थ्य का विश्लेषण किया।

- टमाटर ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए बहुत लाभकारी होता है।
- टमाटर खान से स्किन जवां देखती है और त्वचा से संबंधित रोग नहीं होते है। यानी टमाटर आपको जवां रखता है।
- चीन और जापान के अनुसंधानकर्ताओं द्वारा किए गए अध्ययन में पाया गया कि अन्य फलों और सब्जियों के सेवन से यह लाभ नहीं मिलता। मानसिक रूप से स्वस्थ रहने में गोभी गाजर प्याज और कद्दू में बहुत कम लाभदायक हैं या बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं हैं।
- उन्होंने पाया कि जो लोग एक हफ्ते में दो से छह बार टमाटर खाते हैं उन्हें उन लोगों की तुलना में अवसाद से पीडित होने का खतरा 46 प्रतिशत कम होता है जो हफ्ते में केवल एक बार टमाटर खाते हैं अथवा नहीं खाते। अनुसंधानकर्ताओं ने इसके लिए 70 अथवा उससे अधिक उम्र के करीब 1000 पुरूष और महिलाओं के भोजन की आदत और उनके मानसिक स्वास्थ्य का विश्लेषण किया।
- टमाटर में एंटीआक्सीडेंट रसायन काफी होता है जो कुछ बीमारियों से बचाने में मददगार होता है।

हाजमा दुरस्त करती है अदरक

अदरक का भारतीय मसालों में खूब प्रयोग किया जाता है। यही नही अदरक मॉनसून सीजन में बीमारियों से भी बचती है। अदरक में कैल्शियल, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम जिंक आदि मिनरल भरपूर मात्रा में पाये जाते हैं। तो आइए जानते हैं अदरक के लाभकारी गुणों के बारे में

- अदरक का रस कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखता है, जिससे दिल की बीमारी की संभावना घट जाती है। अगर अदरक नियमित रूप से सेवन हो तो पाचन संबंधी समस्याएं जैसे- गैस, बदहजमी, अपच दूर हो जाती है।
- बीमारियों से जैसे नाक से पानी बहना, सिरदर्द और सर्दी को तुरंत दूर कर देती है। एक कप अदरक, शहद और तुलसी के पत्तो वाली याय बनाकर पीने से जुखाम में राहत मिलती है।
- अगर जोडो के दर्द से परेशान है तो सूखी अदरक के पाउडर का सेवन करने से जोडो में पैदा होने वाली सूजन और दर्द से छुटकारा मिलता है। अदरक में कैल्शियल, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम जिंक आदि मिनरल भरपूर मात्रा में पाये जाते हैं।
- त्वचा में चमक लाये- चेहरे पर अदरक का पेस्ट लगाकर कुछ देर छोड दें। फिर पानी से धो लें कुछ ही दिनों में चेहरा चमकने लगेगा।
- अदरक के 10 से 20 मिलीलीटर रस में गुड मिलाकर सुबह-सुबह पी लें। इससे सभी प्रकार की सूजन जल्दी ही कम हो जाती है।

आंखों को स्वस्थ रखने के लिए रोजाना खाएं संतरा

अगर आप अपनी उम्र के साथ अपनी आंखों को स्वस्थ रखना चाहते हैं और अपनी दृष्टि नुकसान को रोकना चाहते हैं, तो हर रोज एक संतरे का सेवन काफी मददगार हो सकता है। ऐसा एक शोध में सामने आया है। आंख में मैकुलर क्षय उम्र से जुड़ी हुई एक स्थिति है, जिससे दृष्टि क्षेत्र के केंद्र में दिखाई देने में दिक्कत आती है। शोध के नतीजे बताते हैं कि जिन लोगों ने हर रोज कम से कम एक बार संतरे खाए, उनमें 15 साल बाद मैकुलर क्षय के विकसित होने की संभावना 60 फीसदी कम रही। यह प्रभाव संतरे में मौजूद फ्लेवोनवाएड्स की वजह से हैं, जो दृष्टि हानि को रोकता है। फ्लेवोनवाएड्स प्रभावशाली एंटीऑक्सिडेंट होते हैं, जो करीब सभी फलों और सब्जियों में पाए जाते हैं। यह इम्यून सिस्टम के लिए फायदेमंद है। सिडनी विश्वविद्यालय की बामिनि गोपीनाथ ने कहा, हमने पाया कि जिन लोगों ने हर रोज संतरे खाए थे, उनमें कभी संतरे नहीं खाने वालों की तुलना में मैकुलर क्षय होने का खतरा कम था। उन्होंने कहा, यहां तक कि हफ्ते में एक बार संतरा खाने से भी महत्वपूर्ण लाभ दिखाई देता है। इस शोध को अमेरिकी पत्रिका, क्लिनिकल न्यूट्रिशन में प्रकाशित किया गया है। इसमें शोध दल ने 2000 लोगों पर अध्ययन किया, जिनकी आयु 50 साल से ऊपर थी।

टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए लिएंडर पेस और विजय अमृतराज, पहले एशियाई भी बने

नई दिल्ली (एजेंसी)। विश्व के पूर्व नंबर एक युगल खिलाड़ी लिएंडर पेस तथा भारत के प्रसारक और प्रमोटर विजय अमृतराज अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष बन गए हैं। इन दोनों के अलावा प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक रिचर्ड इवांस को भी टेनिस के इस विशेष सम्मान से सम्मानित किया गया है। पुरुष युगल और मिश्रित युगल में 18 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पेस को खिलाड़ियों के वर्ग में जबकि अमृतराज और ग्रेट ब्रिटेन के इवांस को टेनिस में योगदान देने वालों के वर्ग में चुना गया है।

टेनिस खेल से जुड़े इन तीनों दिग्गज को शनिवार को न्यूपोर्ट में अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल आफ फेम में शामिल किया जाएगा। अभी तक 27 देश के 264 लोगों को टेनिस हॉल आफ फेम में शामिल किया गया है। भारत इस तरह से इसमें

प्रतिनिधित्व करने वाला 28वां देश बन जाएगा। पेस ने कहा,''मेरे लिए जिंदगी का सबसे बड़ा सम्मान उस खेल में तीन दशक तक अपने देश का प्रतिनिधित्व करना है, जिसने मुझे सब कुछ दिया और सिखाया। यह सम्मान प्रत्येक टेनिस खिलाड़ी के योगदान को मान्यता मिलना है।

अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल आफ फेम में शामिल होना केवल मेरा ही नहीं करोड़ों भारतीयों का भी सम्मान है। तीन दशक तक चले अपने करियर में पेस युगल रैंकिंग में शीर्ष पर भी रहे और इस दौरान उन्होंने 18 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते। इनमें आठ युगल और 10 मिश्रित युगल खिताब शामिल हैं। वह इन दोनों वर्गों में करियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाले तीन खिलाड़ियों में शामिल हैं।

टेनिस में सर्वाधिक मिश्रित युगल ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने का रिकॉर्ड संयुक्त रूप से पेस और उनकी पूर्व जोड़ीदार मार्टिना नवरातिलोवा के नाम पर दर्ज है। पेस 462 सप्ताह तक एटीपी युगल रैंकिंग में शीर्ष 10 में शामिल रहे। इनमें से 37 सप्ताह वह नंबर एक पर काबिज रहे। उन्होंने अपने करियर में एटीपी टूर में कुल 55 युगल खिताब जीते। पेस ने 30 वर्ष तक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने डेविस कप में रिकॉर्ड 45 मैच जीते हैं। इसके अलावा उन्होंने 1996 में अटलांटा ओलंपिक खेलों में एकल में कांस्य पदक जीता था। अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ़ फेम की मानद अध्यक्ष किम क्लाइस्टर्स ने कहा कि मैं लिएंडर पेस, विजय अमृतराज और रिचर्ड इवांस को अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए चुने जाने पर बधाई देते हुए रोमांचित महसूस कर रही हूं। इन तीनों दिग्गज ने टेनिस में अपनी विशेष छाप छोड़ी है और विश्व स्तर पर इस खेल को बढ़ावा देने में अहम योगदान दिया है।

स्पेन के खिलाफ अभियान की शुरुआत करेगी भारतीय टीम

वालेंसिया (एजेंसी)। भारतीय पुरुष और महिला हॉकी 15 से 22 दिसंबर तक खेले जाने वाले पांच देशों के टूर्नामेंट वालेंसिया 2023 में भाग लेने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। टूर्नामेंट में भाग लेने वाली अन्य टीमें स्पेन, बेल्जियम, जर्मनी, आयरलैंड और फ्रांस हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम 15 दिसंबर को टूर्नामेंट के पहले गेम में मेजबान स्पेन से भिड़ेगी और 16 दिसंबर को बेल्जियम, 19 दिसंबर को जर्मनी और अपने आखिरी मैच में 21 दिसंबर को आयरलैंड से भिड़ेगी। स्पेन के खिलाफ अपने पहले मैच से पहले, भारतीय महिला टीम की कप्तान सविता ने कहा, 'हमें वालेंसिया पहुंचे हुए तीन दिन हो गए हैं, हमारी अनुकूलन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब हम स्पेन के खिलाफ टूर्नामेंट शुरू करने के लिए तैयार हैं। हमें कुछ का सामना करना पड़ेगा। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग वाली टीमें और इस अवसर का उपयोग आगामी एफआईएच हॉकी ओलंपिक क्वालीफायर रांची 2024 की तैयारी में अपनी कमजोरियों पर काम करने के लिए करें। हम हर खेल में अपना दिल खोलकर खेलेंगे क्योंकि यह हमारे प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए सही मंच है।

इसी तरह, भारतीय पुरुष हॉकी टीम अपने पांच देशों के टूर्नामेंट वालेंसिया 2023 अभियान को समाप्त करने के लिए 15 दिसंबर को पहले मैच में मेजबान स्पेन से भिड़ेगी, उसके बाद 16 दिसंबर को बेल्जियम, 19 दिसंबर को जर्मनी और 20 दिसंबर को फ्रांस के खिलाफ मुकाबला करेगी।

भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह भी अपने पहले मैच से पहले अपने प्रदर्शन को लेकर आश्वस्त हैं। उन्होंने कहा, 'कुछ शीर्ष हॉकी टीमें वेलेंसिया आई हैं, वे सभी अपने खेल को बेहतर बनाने के लिए इस विंडो का उपयोग करने की होड़ में हैं और हम भी अलग नहीं हैं। हम हर मैच को एक महत्वपूर्ण मैच मानेंगे और टूर्नामेंट जीतने का प्रयास करेंगे। टीम फिर से हॉकी खेलने और देश को गौरवान्वित करने के लिए उत्सुक है।

आईपीएल की ब्रांड वैल्यू 10 अरब डॉलर के पार

मुंबई (एजेंसी)। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की कुल ब्रांड वैल्यू 2023 सीजन के बाद 28 प्रतिशत बढ़कर 10.7 बिलियन डॉलर (लगभग 89,232 करोड़ रुपए) तक पहुंच गई। 2008 में लॉन्च होने के बाद से भारत के प्रमुख खेल आयोजन की ब्रांड वेल्यू 433 प्रतिशत बढ़ी है। ब्रांड वैल्यूएशन कंसल्टेंसी ब्रांड फाइनेंस ने एक रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी है।

रिपोर्ट में वार्षिक क्रिकेट टूर्नामेंट के ब्रांड मूल्य में इस साल की वृद्धि के लिए स्टेडियमों में दर्शकों की भारी संख्या, इंटरनेट और अन्य माध्यमों पर आईपीएल मैचों की अधिक खपत और मेगा-मीडिया साझेदारी को श्रेय दिया गया। कंसल्टेंसी ने मुंबई इंडियंस को इंडियन प्रीमियर लीग में सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी ब्रांड माना जिसकी ब्रॉन्ड वेल्यू 87 मिलियन डॉलर थी।

महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई वाली चेन्नई सुपर किंग्स 81 मिलियन डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ सूची में दूसरे स्थान पर है। कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) और आरसीबी क्रमशः 78.6 मिलियन डॉलर और 69.8 मिलियन डॉलर के साथ तीसरे

और चौथे नम्बर पर आते हैं।

जहां तक ब्रांड वैल्यू का सवाल है तो गुजरात टाइटंस को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है - यह पिछले साल 8वें स्थान से उछलकर इस बार 5वें स्थान पर पहुंच गई है। इस साल इसकी ब्रांड वैल्यू 38 प्रतिशत बढ़ी। राजस्थान रॉयल्स (आरआर) और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (आरसीबी) लगातार अपने क्रिकेट ब्रांड का निर्माण कर रहे हैं और हर गुजरते आईपीएल सीजन के साथ मजबूत ब्रांड साबित हुए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि जहां आरआर व्यापक क्रिकेट पेशकश के साथ कई भौगोलिक क्षेत्रों में उपस्थिति के साथ एक वैश्विक टी20 पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर रहा है, वहीं आरसीबी लगातार बहुप्रतीक्षित टीम बनी हुई है जिसके पास कोई आईपीएल ट्रॉफी नहीं है। लखनऊ सुपरजायंट्स (एलएसजी) ने 47 मिलियन डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ 8वां स्थान हासिल किया जोकि 48त की प्रभावशाली वृद्धि के साथ सबसे तेजी से बढ़ने वाला आईपीएल ब्रांड है। ब्रांड फाइनेंस के अनुसार महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) की शुरूआत ने टीमों के संबंधित ब्रांड मूल्यों को बढ़ावा दिया। रिपोर्ट में कहा गया है, 52 मैच दिन, प्रभाव खिलाड़ी नियम और निर्णय समीक्षा प्रणाली (डीआरएस) सहित उल्लेखनीय बदलाव आईपीएल 2023 दर्शकों में नया उत्साह लाते हैं।

भारत के अनूप देशमुख नें जीता जाफना इंटरनेशनल शतरंज का खिताब

जाफना , श्रीलंका (एजेंसी)। श्रीलंका के उत्तरी हिस्से की राजधानी जाफना में सम्पन्न हुए जाफना इंटरनेशनल टूर्नामेंट का खिताब भारत के 56 वर्षीय इंटरनेशनल मास्टर अनूप देशमुख नें अपने नाम कर लिया है। कुल 747 खिलाड़ियों के बीच हुए इस टूर्नामेंट में 10 राउंड के बाद अपराजित रहते हुए 8 जीत और 2 ड्रॉ के साथ अनूप देशमुख नें 9 अंक बनाते हुए बेहतर टाईब्रेक के आधार पर पहला स्थान हासिल किया , इस दौरान उन्होने बेहद महत्वपूर्ण नौवे राउंड में टॉप सीड 2400 रेटेड श्रीलंका के दिलशान लियांगे को पराजित किया। भारत के ही अनुभवी इंटरनेशनल मास्टर शेखर चन्द्र साहू भी 9 अंक बनाकर दूसरे स्थान पर रहे जबकि श्रीलंका के इसरु अलहकून 8.5 अंक बनाकर तीसरे स्थान पर रहे।

12 साल से ज्यादा जीने की उम्मीद नहीं थी, कैमरन ग्रीन ने गंभीर बीमारी का किया खुलासा

पर्थ (एजेंसी)। ऑस्ट्रेलिया के आलराउंडर कैमरन ग्रीन ने खुलासा किया कि जब वह पैदा हुए थे तो वह 'इरिवर्सिबल क्रॉनिक किडनी रोग से पीड़ित थे। ऑस्ट्रेलिया के इस दुबले पतले हरफनमौला खिलाड़ी ने कहा कि एक समय उनके 12 साल से ज्यादा जीने की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कहा कि इस बीमारी के कोई लक्षण नहीं होते और इसमें किडनी (वृक्क) को ठीक भी नहीं किया जा सकता।

ग्रीन ने कहा, 'जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे माता पिता को बताया गया कि मुझे 'इरिवर्सिबल क्रॉनिक किडनी बीमारी है जिसके कोई लक्षण नहीं होते लेकिन अल्ट्रासाउंड के जरिये इसका पता चला। उन्होंने कहा, 'क्रॉनिक किडनी बीमारी बढ़ती रहती है। दुर्भाग्य से मेरा गुर्दा अन्य लोगों के गुर्दे की तरह खून को साफ नहीं करता। यह 24 साल का खिलाड़ी आस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम का अहम सदस्य है। ग्रीन ने कहा कि उनका 'किडनी फंक्शन इस समय 60 प्रतिशत है जो दूसरे चरण में है और पांचवें चरण में प्रत्यारोपण या 'डायलिसिस' की जरूरत होती है।

उन्होंने कहा, 'मैं अभी बीमारी के दूसरे चरण में हूं लेकिन अगर आप अच्छी तरह देखभाल नहीं करोगे तो यह स्तर और नीचे चला जाएगा। किडनी सही नहीं हो सकती। इसे ठीक नहीं किया जा सकता। इसलिए आप बीमारी के बढ़ने को धीमा करने के तरीके ढूंढ सकते हो, आप कोशिश करते हो। ग्रीन की मां टार्सी को गर्भावस्था के 19वें हफ्ते के स्कैन में इस बीमारी का पता चला था। ग्रीन के पिता गैरी ने कहा, 'उस समय इसके बारे में ज्यादा पता नहीं था। तब उसके 12 वर्ष से अधिक जीने की उम्मीद नहीं थी।

तेज गेंदबाजी आल राउंडर ग्रीन ने 2020 में आस्ट्रेलिया के लिए पदार्पण किया था और तब से 24 टेस्ट, 23 वनडे और आठ टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं। उन्होंने कहा कि इस बीमारी के कारण उनका क्रिकेट करियर भी प्रभावित हुआ है क्योंकि उन्हें मांसपेशियों में खिंचाव बहुत जल्दी हो जाता है। उन्होंने कहा, 'मुझे नमक और प्रोटीन कम रखना पड़ता है जो बतौर क्रिकेटर आदर्श स्थिति नहीं है लेकिन जब मैच होते हैं तो मैं प्रोटीन थोड़ा ज्यादा लेने लगता हूं क्योंकि मैं मैदान पर काफी ऊर्जा खर्च करता हूं। बस खुद की देखभाल का सही तरीका ढूंढना पड़ता है।

बड़े मियां छोटे मियां से जुड़ा पृथ्वीराज सुकुमारन का नाम

अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ अभिनीत आगामी एक्शन-कॉमेडी बड़े मियां छोटे मियां की योजना लंबे समय से चल रही है। अली अब्बास जफर द्वारा निर्देशित फिल्म की घोषणा 2022 में की गई थी, जहां निर्माताओं ने एक संक्षिप्त टीजर जारी किया था। टीजर से दर्शकों को फिल्म की दृश्य शैली और एक्शन के पैमाने की झलक देखने को मिली थी। कथित तौर पर, मलयालम स्टार पृथ्वीराज सुकुमारन को फिल्म में विलेन की भूमिका निभाने के लिए चुना गया है। अब, फिल्म के मुख्य कलाकारों के बारे में नए विकास की रिपोर्टें ऑनलाइन सामने आ रही हैं। इससे पहले, यह अफवाह थी कि फिल्म अंततः अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ के बीच क्लाइमेक्टिक अदायगी का कारण बनेगी। हालांकि, अब ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ मिलकर एक बुरी ताकत के खिलाफ काम करेंगे, जिसका किरदार कथित तौर पर पृथ्वीराज निभाएंगे।

द बकिंघम मर्डर्स में मां का किरदार कर असहज महसूस कर रही थीं करीना

अभिनेत्री करीना कपूर इन दिनों अपने आगामी प्रोजेक्ट्स को लेकर चर्चा में हैं। जल्द ही अभिनेत्री फिल्म सिंघम अगेन और नेटफ्लिक्स फिल्म द बकिंघम मर्डर्स में नजर आएंगी। हाल ही में दिए इंटरव्यू में करीना ने हंसल मेहता की फिल्म के बारे में जानकारी साझा की। इसके अलावा उन्होंने अपने किरदार को लेकर भी कई खुलासे किए हैं। बातचीत के दौरान करीना कपूर ने कहा कि द बकिंघम मर्डर्स फिल्म में उनका किरदार एक दु:खी मां का है। करीना ने अपनी फिल्म की कहानी के बारे में बताते हुए कहा, फिल्म की शुरुआत में एक दुखद घटना दिखाई जाती है, जिसमें उनके किरदार के बच्चे को गोली मार दी जाती है। जिसके बाद कहानी में एक नया मोड़ आता है। इस घटना के बाद मैं अपने गृहनगर से भागकर, दूसरे शहर में पहुंच जाती हूं।

करीना ने कहा, मुझे यह किरदार बहुत पसंद आया, क्योंकि यह पहली बार है जब मैं एक जासूस का किरदार निभा रही हूं। मैं क्राइम ड्रामा की बहुत बड़ी फैन हूं। हालांकि, इस किरदार को निभाना मेरे लिए काफी कठिन था। क्योंकि इस किरदार के दु:ख ने मुझे असहज कर दिया था। अभिनेत्री ने आगे बताया कि उन्होंने निर्देशक से द बकिंघम मर्डर्स के चार भागों की सीरीज बनाने के लिए कहा है, क्योंकि वे इस किरदार को छोड़ना नहीं चाहती हैं। ओटीटी डेब्यू को लेकर करीना कपूर ने कहा, जब मैं ओटीटी डेब्यू करने के लिए तैयार थी। उस समय मैं बहुत परेशान थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पहली बार स्क्रीन पर आ रही हूं। यह वैसा ही था जैसा मैंने 24 साल पहले महसूस किया था। उन्होंने आगे बताया कि ओटीटी प्लेटफॉर्म और फीचर फिल्मों के लिए काम करने के बीच का अंतर ही उन्हें परेशान करता है। वे ओटीटी प्रोजेक्ट्स पर काम करने के बाद भी काफी नर्वस हैं। फिल्म के बारे में बात करें तो द बकिंघम मर्डर्स का निर्देशन हंसल मेहता ने किया है। इसकी कहानी असीम अरोड़ा, कश्यप कपूर और राघव राज कक्कड़ ने लिखी है। करीना कपूर ने बालाजी टेलीफिल्म्स और टीबीएम फिल्म्स ने इस फिल्म का निर्माण किया है। इस फिल्म में करीना कपूर पुलिस की भूमिका में दिखेंगी।

तब मैं निर्माता से कह दूंगा कि अब मुझे छोड़ दो, अच्छा काम करने के लिए कम काम करना होगा

पंकज त्रिपाठी फिल्मी दुनिया से लेकर ओटीटी तक के दर्शकों से प्यार बटोर रहे हैं। पंकज आज फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा नाम बन चुके हैं जिन्हें हर कोई देखना काफी पसंद करता है। इस वक्त पंकज त्रिपाठी ओटीटी पर रिलीज हुई कड़क सिंह को लेकर चर्चा में हैं। उन्होंने कहा है कि अब अच्छा काम करने के लिए काम कम करना होगा।

आमतौर पर कलाकार या तो ओटीटी पर अच्छा कर रहे होते हैं या फिर बड़े पर्दे पर। मगर आप सिनेमा और ओटीटी दोनों पर लोकप्रिय हैं। इसका क्या राज है?

कोई राज नहीं है। मैं सिनेमा और ओटीटी दोनों ही करता हूं। इस साल की तीसरी फिल्म कड़क सिंह अब जी 5 पर आ रही है। अगले साल मैं फिर से थिएटर से शुरुआत करूंगा। फिर दो महीने बाद ओटीटी पर आ जाऊंगा, फिर उसके बाद सिनेमा और फिर ओटीटी पर। इस तरह मैं बैलेंस बनाकर चलता हूं। ओटीटी पर लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, तो सिनेमा वाले भी पूछने लगे। यह दोनों के बीच एक संतुलन है और मैं दोनों का हिस्सा बनता हूं। हालांकि फिल्म साइन करते वक्त मैं सिनेमा या ओटीटी की बजाय उसकी स्क्रिप्ट पर ध्यान देता हूं। मुझे बस कहानी पसंद आनी चाहिए। कहानी पसंद आ जाए, तो फिर मैं उसे हां बोल देता हूं, फिर वह फिल्म चाहे ओटीटी पर आए या सिनेमा पर।

इस साल आपकी दो सीक्वल फिल्में रिलीज हो चुकी हैं। इनके अलावा भी आप कई और सीक्वल फिल्मों व सीरीज का हिस्सा हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि इतने सीक्वल करने के बाद आपको नया काम करने के लिए कम वक्त मिलता है?

हां, बीच में कुछ ऐसा हो गया था। मैंने पांच-छह सीक्वल किए थे। पहले मिर्जापुर हुआ, फिर फुकरे 3, OMG 2, स्त्री 2 और फिर क्रिमिनल जस्टिस 4, तो मैं भी एक दिन परेशान हो गया कि इतना मैं 2, 3, 4 क्यों कर रहा हूं। (हंसते हुए) अभी मैट्रो 2 भी है, जिसे बताना मैं भूल ही गया था। तो इस तरह मैं 6-7 सीक्वल कर रहा हूं। भला यह भी कोई सिनेमा है? कोई पूछेगा कि क्या कर रहे हो? तो मैं कहूंगा कि 7 फिल्में कर रहा हूं। कौन सी 7 फिल्में? 2, 3, 4, 5, 6.....। ऐसा मैंने कभी प्लान नहीं किया था। अभी जब तक चल रहा और मैं बोर नहीं हो रहा हूं, तब तक ऐसे ही चलेगा, वरना मैं निर्माता से कह दूंगा कि अब मुझे छोड़ दो। मैंने ऐसा भी दौर देखा है, जब 8 साल तक मुंबई में कैमरे के सामने आने के लिए भटक रहा था। वहीं अब 7 फ्रेंचाइजी में काम कर रहा हूं।

रजनीकांत की 170वीं फिल्म का टाइटल आया सामने, अमिताभ बच्चन संग आएंगे नजर

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत सालों बाद एक साथ पर्दे पर साथ नजर आने वाले हैं। बीते दिनों रजनीकांत की 170वीं फिल्म में अमिताभ बच्चन की एंट्री की घोषणा की गई थी। यह जोड़ी करीब 32 साल बाद किसी फिल्म में साथ नजर आने वाले हैं। अब रजनीकांत और अमिताभ बच्चन की इस फिल्म का टाइटल भी सामने आ गया है। टीजे ग्नानवेल द्वारा लिखित और निर्देशित इस फिल्म का नाम वेट्टैयन रखा गया है। प्रोडक्शन बैनर लाइका प्रोडक्शंस ने टाइटल टीजर वीडियो में फिल्म के नाम का खुलासा किया है। फिल्म के टाइटल टीजर क्लिप में रजनीकांत स्टाइलिश रूप से काले धूप के चश्मे लगाए हुए दिखाई दे रहे हैं और कह रहे हैं, जब शिकार जारी है, तो शिकार को गिरना ही चाहिए। इसके बाद शुबा द्वारा लिखित और गाया गया एक छोटा रैप है, जिसे अनिरुद्ध रविचंदर द्वारा संगीतबद्ध किया गया है। बता दें कि अमिताभ बच्चन और रजनीकांत ने अंतिम बार साल 1991 में रिलीज फिल्म हम में काम किया था।

संक्षिप्त समाचार

सिग्नेचर ब्रिज पर चलते ऑटो पर जानलेवा स्टंट, साइकिल सवार को मारी टक्कर

नईदिल्ली, एजेंसी। उत्तरी दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज पर स्टंट में शामिल ऑटो-रिक्शा को जब्त कर लिया गया है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। ऑटो-रिक्शा सवार एक व्यक्ति वाहन से बाहर निकल कर स्टंट कर रहा था, इस दौरान वह एक साइकिल सवार व्यक्ति से टकरा गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, संबंधित ऑटोरिक्शा और गाजियाबाद के रहने वाले उसके चालक शिवा का टीपीआर सर्कल के यातायात कर्मियों ने पता लगा लिया है। पुलिस ने कहा कि खतरनाक तरीके से वाहन चलाने, बिना लाइसेंस के वाहन चलाने और मोटर वाहन अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं के तहत चालान जारी किया गया तथा ऑटो-रिक्शा को जब्त कर लिया गया है। इससे पहले सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू कर दी थी। पुलिस ने टीपीआर सर्कल के ट्रैफिक कर्मियों ने उसके पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) नंबर की मदद से ऑटो रिक्शा को ट्रैक किया। हादसे के बाद ऑटोरिक्शा मौके से फरार हो गया था। एक यातायात अधिकारी ने बताया कि स्टंट कर रहा व्यक्ति जिस साइकिल चालक से टकराया था, उसे कोई गंभीर या ज्यादा चोट नहीं आई है। मोटरसाइकिल सवार चालक के हेलमेट में लगे कैमरे से रिकॉर्ड किए गए वीडियो में एक व्यक्ति तेज रफ्तार तिपहिया वाहन से लटकते हुए और एक साइकिल सवार व्यक्ति को टक्कर मारते हुए देखा जा रहा था। एक यूजर ने 14 घंटे पहले इंस्टाग्राम पर घटना के वीडियो को शेयर किया है। जिसपर कमेंट करते हुए लगभग सभी लोगों ने दिल्ली पुलिस को टैग करते हुए स्टंट करने वाले पर एक्शन लेने का अनुरोध किया है। वहीं एक यूजर ने लिखा है कि बेचारा साइकिल वाला। किया किसी और ने और भुगता किसी और ने। दूसरे यूजर ने लिखा है, दिल्ली पुलिस प्लीज इसपर गौर फरमाएं, इससे नागरिकों की जिंदगी पर खतरा है।

मुरादनगर में अंबेडकर की मूर्ति तोड़ने पर विवाद, गांव में फोर्स तैनात

नईदिल्ली, एजेंसी। गाजियाबाद के मुरादनगर थाना क्षेत्र के गांव सुठारी में अंबेडकर प्रतिमा तोड़े जाने की घटना सामने आई है। गांव के ही असामाजिक तत्वों ने स्टेचू को तोड़ दिया। इस घटना के बाद दलित समाज के लोगों में रोष व्याप्त है। तनाव को देखते हुए गांव में भारी पुलिस फोर्स मौजूद है। गांव सुठारी में डॉ बी आर अंबेडकर पार्क स्थित है। पार्क में डॉ अंबेडकर की प्रतिमा लगी हुई है। इसको लेकर दलित समाज में अन्य लोगों में काफी समय से विवाद चलता आ रहा है। इस बात को लेकर कई बार गांव में पंचायत भी हुई। गुरुवार सुबह को जब लोग आंबेडकर पार्क की ओर पहुंचे तो वहां पर डॉ भीमराव की खंडित प्रतिमा देखकर दंग रह गए। इसके बाद दलित समाज के लोग एकत्र हो गए और हंगामा करना शुरू कर दिया। दलित समाज के लोगों का आरोप है कि गांव के दबंगों ने जो काफी समय से प्रतिमा लगाने का विरोध कर रहे थे। उन्होंने ही प्रतिमा को खंडित किया है। डॉ भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा खंडित होने की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी मौके पर पहुंच गए और लोगों को समझा बूझकर शांत किया। तनाव को देखते गांव में पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है।

कार और बाइक चालक हो आएं सावधान! अब पेट्रोल पंप पर पकड़े जाएंगे बिना पीयूसी के चलने वाले वाहन

नईदिल्ली, एजेंसी। आने वाले दिनों में प्रदूषण पर सख्ती और बढ़ने जा रही है। ऐसे में बगैर प्रदूषण जांच प्रमाणपत्र (पीयूसी) के चलने वाले वाहनों की अब खैर नहीं है। दिल्ली परिवहन विभाग अब बगैर पीयूसी वाले वाहनों के चालान के लिए पेट्रोल पंप पर कैमरे लगाएगा। चार पेट्रोल पंपों पर यह पायलट प्रोजेक्ट सफल हो चुका है। अब इनकी संख्या में विस्तार कर 25 और पेट्रोल पंपों पर कैमरे लगवाए जाएंगे। कैमरे के जरिये ही ऐसे वाहनों को ई-चालान भेजने की भी तैयारी है। अभी पायलट योजना के तहत 850 से अधिक वाहनों को सिर्फ नोटिस भेजे गए हैं। गौरतलब है कि बगैर प्रदूषण जांच वाले वाहनों के पकड़े जाने पर 10 हजार रुपये के चालान का प्रावधान है। भविष्य में चरणबद्ध तरीके से 500 पेट्रोल पंप पर कैमरे लगवाए जाएंगे। परिवहन विभाग ने बीते अक्टूबर में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चार पेट्रोल पंप पर बगैर प्रदूषण जांच वाले वाहनों को पकड़ने के लिए कैमरे लगाए थे। ये कैमरे मॉडल टाउन के दो पेट्रोल पंप, यमुना विहार और गुलाबी बाग के एक-एक पेट्रोल पंप पर लगाए गए थे। अभी तक वहां आए कुल वाहनों में 16 वाहन ऐसे चिह्नित किए गए, जिन्होंने प्रदूषण जांच नहीं कराई थी। इनमें 850 से अधिक वाहनों को चालान भेजे हैं। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार और ट्रैफिक पुलिस शहर में वायु प्रदूषण की जांच और नियंत्रण के लिए कई अहम कदम उठा रही है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, एनजीटी, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण विभाग/दिल्ली प्रदूषण द्वारा जारी निर्देशों को लागू करना शामिल है। बता दें कि, भारत में चलने वाले वाहनों के लिए वैध पीयूसीसी होना और उनके चालकों के लिए इसकी एक कॉपी रखना अनिवार्य है। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य केवल उन्हीं वाहनों को सड़कों पर चलने की अनुमति देना है, जो केंद्र सरकार द्वारा विनियमित उत्सर्जन मानदंडों का पालन कर रहे हैं।

जीपीएस से मिलेगा बिजली कनेक्शन

नईदिल्ली, एजेंसी।
प्रदेश सरकार के आदेश पर दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने इस माह अवैध कॉलोनियों में बिजली कनेक्शन देने की नीति जारी कर दी है। हालांकि अवैध कॉलोनी की रजिस्ट्री भी नहीं है, न ही कॉलोनियों का नामकरण हुआ है। इस वजह से बिजली निगम जीपीएस लोकेशन को आधार बनाकर बिजली कनेक्शन देने की तैयारी कर रहा है। दो दिसंबर को दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम मुख्यालय ने अवैध कॉलोनियों और स्लम बस्तियों में बिजली कनेक्शन देने का आदेश जारी कर दिया था।

इसके बाद शहर की अवैध कॉलोनियों में प्लॉट लेने वाले हजारों लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई थी। इसके साथ ही बिजली निगम के अधिकारियों ने भी राहत की सांस ली थी। इस आदेश के बाद लोगों ने बिजली निगम के उपमंडल कार्यालयों में बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन देने शुरू कर दिए हैं। आवेदन मिलने के बाद अब विभागीय अधिकारियों के सामने आवेदक के पते को लेकर समस्या आ रही है। अवैध होने के कारण अभी इन कॉलोनियों का नामकरण नहीं हुआ है। प्लॉटों की रजिस्ट्री भी नहीं हुई है। इस वजह से राजस्व रिकॉर्ड भी नहीं है।

कॉलोनियों और इनके प्लॉट धारकों का नगर निगम के पास भी रिकॉर्ड नहीं है। नगर निगम के पास भी इनका रिकॉर्ड नहीं है। ऐसे में यदि आवेदन के आधार पर ही यहां पर कनेक्शन जारी हो गए तो भविष्य में बिजली बिल की वसूली में समस्या खड़ी होगी। वहीं अवैध कॉलोनियों में बिजली कनेक्शन देने से 10 मेगावाट तक बिजली का लोड बढ़ेगा। बिजली निगम इस समस्या से निपटने के लिए प्लॉट की जीपीएस लोकेशन को आधार बनाने पर विचार कर रहा है, ताकि सरकार की नीति पर अमल किया जा सके। इलाके के जेई कॉलोनियों में जाकर जीपीएस लोकेशन लेकर सत्यापित करेंगे। बिजली निगम अवैध कॉलोनियों में लगने वाले बिजली खंभों की जीआईएस (जियोग्राफिक इनफोर्मेशन सिस्टम) कोडिंग करेगा।

बिजली कनेक्शन के लिए जमीन के मालिकाना हक का दस्तावेज होना चाहिए। इसके बाद बिजली निगम की वेबसाइट पर आवेदन किया जाता है। इसके अलावा लोड के लिए निर्धारित शुल्क जमा किया जाता है।

वैध इलाकों में बिजली निगम अपने स्तर पर बिजली का आधारभूत ढांचा विकसित करता है या संबंधित बिल्डर या एजेंसी से बिजली का आधारभूत ढांचा विकसित करने के लिए कहता है। लेकिन, अवैध कॉलोनियों में बिजली कनेक्शन देने से पहले बिजली लाइन खींचने के लिए विभाग की ओर आवेदकों से ही बजट लिया जाता है। अब सरकार की ओर से कनेक्शन देने का आदेश आया है तो विभागीय अधिकारी उलझन में हैं कि बिजली निगम अपने खर्चे पर पर इन कॉलोनियों में लाइन खड़ी करेगा या फिर बिजली कनेक्शन के लिए आवेदकों से शुल्क ले। उधर, बिजली निगम की वेबसाइट में भी अवैध कॉलोनियों में कनेक्शन देने के लिए सुधार की कार्रवाई चल रही है। डीएचबीवीएन के अधीक्षण अभियंता नरेश कुमार कक्कड़ ने कहा, अवैध कॉलोनियों का नगर निगम और राजस्व विभाग के पास इनका रिकॉर्ड नहीं है। यह एक समस्या है।

नए नोएडा की अड़चनें हो गईं दूर? मास्टर प्लान-2041 को लेकर सभी आपत्तियों का निस्तारण

नईदिल्ली, एजेंसी।
ग्रेटर नोएडा के दादरी और बुलंदशहर के गांवों की जमीन पर बसने वाले नए नोएडा के मास्टर प्लान-2041 को लेकर आई आपत्तियों का निस्तारण नोएडा प्राधिकरण ने कर दिया है। अब मास्टर प्लान को मंजूरी देने का प्रस्ताव नोएडा प्राधिकरण की आगामी बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। वहीं, नोएडा की तर्ज पर ही नए नोएडा के लिए जमीन अधिग्रहण करने की तैयारी है।

नए नोएडा के मास्टर प्लान-2041 को लेकर करीब 19 आपत्तियां आईं थीं। लोगों ने घर-स्कूल के शिफ्ट करने की पॉलिसी, वेयर हाउस को शिफ्ट करने के तरीके समेत अलग-अलग मामलों को लेकर आपत्ति की थीं। इन सभी आपत्तियों का जवाब प्राधिकरण ने दे दिया है।

अब इस मास्ट प्लान को इसी महीने होने वाली बोर्ड बैठक में मंजूरी के लिए रखा जाएगा, जिसके बाद शासन को भेजा जाएगा। वहीं, दूसरी ओर नए नोएडा के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया क्या होगी, यह अभी तय नहीं हो सका है। संभावना है कि नोएडा में हो रखी अधिग्रहण की प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। यहां पर प्राधिकरण सीधे किसानों से सहमति के अलावा जिला प्रशासन के जरिए धारा-4 व 6 प्रक्रिया के तहत भी जमीन लेता है।

यह दोनों प्रक्रिया वहां भी अपनाई जाएगी। इसके अलावा प्राधिकरण सहित अगर दूसरे तरह के विकासकर्ता आते हैं तो उनके लिए भी सीधे किसानों से सहमति का विकल्प भी खुला रखा जाएगा। इस बारे में नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ सतीश पाल का कहना है कि अभी नोएडा की तर्ज पर ही वहां भी जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया अपनाने पर विचार किया जा रहा है। जल्द ही कोई निर्णय ले लिया जाएगा। गौरतलब है कि नए नोएडा के विकसित होने से निवेश बढ़ेगा। वहीं, नोएडा प्राधिकरण के सीईओ डॉ. लोकेश एम ने बुधवार को सेक्टर-137 से लेकर बरौला, सलारपुर एरिया का निरीक्षण किया। इस दौरान सड़क और फुटपाथ की सफाई व्यवस्था पूरी तरह खराब मिली। इस पर उन्होंने मैकेनिकल स्वीपिंग एजेंसी को ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश दिए। जन स्वास्थ्य विभाग की निगरानी भी सही नहीं मिली।

बारात देखने गई 10 साल की बच्ची रास्ता भटकी, घर पहुंचाने के बहाने कार में गैंगरेप

नईदिल्ली, एजेंसी।
लोनी में घर के नजदीक मैरिज होम में बारात देखने गई दस साल की बच्ची के साथ कार सवार दो बदमाशों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। बच्ची रास्ता भटककर राशिद गेट के पास पहुंच गई थी। बदमाशों ने उसे घर पहुंचाने के बहाने कार में बैठाकर वारदात को अंजाम दिया। बच्ची की मां ने बुधवार को अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है।

लोनी की एक कॉलोनी में रहने वाली महिला शादी समारोह में काम करके अपना घर चलाती है। महिला ने बताया कि 10 दिसंबर की शाम करीब छह बजे उसकी 10 वर्षीय बेटी मोहल्ले के दूसरों बच्चों के साथ नजदीक के मैरिज होम में बारात देखने के लिए घर से निकली थी। रास्ता भटककर लोनी थाने के राशिद अली गेट के पास पहुंच गई। गेट के पास ईको कार सवार दो बदमाशों ने बच्ची को घर पहुंचाने का झांसा देकर कार में बैठा लिया।

बदमाश बच्ची को घर ले जाने के बजाय लोनी निठोरा मार्ग पर ले गए। यहां सुनसान स्थान पर बच्ची के साथ कार में ही सामूहिक दुष्कर्म किया। फिर रात में ही एक आरोपी निठोरा रोड स्थित विजयनगर कॉलोनी के पास उतर गया। जबकि दूसरा बच्ची को राशिद अली गेट के पास छोड़कर फरार हो गया। बच्ची किसी तरह घर पहुंची। एसीपी लोनी सूर्यबली ने बताया कि बच्ची की मां की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गाय है। बच्ची का चिकित्सा परीक्षण कराया गया है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश डाल रही है। घटना के बाद दस दिसंबर की रात बच्ची घर आकर सो गई। 11 दिसंबर की सुबह शक होने पर बच्ची की मां ने उससे पूछताछ की तो उसे घटना की जानकारी हुई।

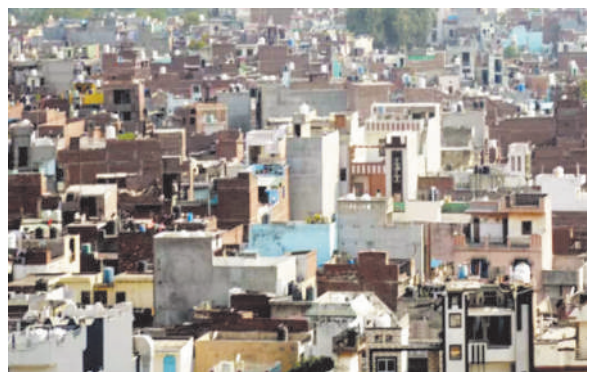

दिल्ली में अवैध कॉलोनियां तोड़ने पर 3 साल के लिए बढ़ेगी रोक, मोदी सरकार संसद में लाई नया बिल

नईदिल्ली, एजेंसी।
दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वालों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार अनधिकृत कॉलोनियों में तोड़फोड़ पर लगी रोक की समय सीमा तीन साल और बढ़ाने जा रही है। अब 31 दिसंबर 2026 तक अनधिकृत कॉलोनियों में तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। केंद्र सरकार ने बुधवार को राजधानी दिल्ली में अनधिकृत विकास पर दंडात्मक कार्रवाई के खिलाफ सुरक्षा को 31 दिसंबर की समय सीमा से तीन साल के लिए बढ़ाने के प्रावधान वाला बिल लोकसभा में पेश कर दिया। अनधिकृत संरचनाओं को छूट देने वाला यह विधेयक केंद्रीय आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पेश किया। विधेयक का उद्देश्य राजधानी दिल्ली में कुछ प्रकार के अनधिकृत विकासों को दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान करना है, जहां अभी तक पर्याप्त उपाय नहीं किए गए हैं। लोकसभा में पेश

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून (विशेष प्रावधान) दूसरा (संशोधन) अधिनियम 2023 अनधिकृत इमारतों को दी गई सुरक्षा को 2026 तक बढ़ाता है। विधेयक पेश करते हुए हरदीप पुरी ने कहा कि इन अनधिकृत कॉलोनियों के लिए विकास नियंत्रण मानदंड 8 मार्च, 2022 को अधिसूचित किए गए हैं। वर्ष 2041 के दिल्ली मास्टर प्लान को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिसमें झुग्गी-झोपड़ी, क्लस्टर, अनधिकृत कॉलोनियों जैसे अनधिकृत विकास के उपाय किए गए हैं। राजधानी में रह रहे लाखों लोगों को फायदा होगा ‑ संसद में इस बिल के पास होने के बाद दिल्ली की 1797 अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लाखों लोगों को फायदा मिलेगा। 2006 में पहली बार लाया गया था विधेयक ‑ अनधिकृत कॉलोनियों में तोड़फोड़ रोकने वाला यह बिल पहली बार 19 मई 2006 को केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय लाया था। शुरुआत में यह बिल एक साल के लिए तोड़फोड़ पर रोक लगाने के लिए लाया गया था, लेकिन बाद में इसी अवधि को बढ़ाने का सिलसिला जारी है। संपत्ति मालिकों को बड़ी राहत ‑ दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का कहना है कि संसद में पेश किए गए बिल का हम स्वागत करते हैं। केंद्रीय मंत्री सरदार हरदीप सिंह पुरी विधेयक में प्रस्तावित तीन साल का एक मुश्त विस्तार दिल्ली के संपत्ति मालिकों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। दिल्ली की अलग-अलग एजेंसियां इन अनिधृत कॉलोनियों को नियमित करने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन ले आउट प्लान नहीं बनने के कारण यह संभव नहीं है। यही वजह है कि लोगों को मालिकाना हक भी नहीं मिल पा रहा है।

15 मिनट 2 हादसे, जलकर खाक हुई 17 गाड़ियां

16 लोगों की मौत, वेनेजुएला हाईवे पर ट्रक की टक्कर के बाद हुआ हादसा

वेनेजुएला, एजेंसी।
वेनेजुएला की राजधानी कराकास के पास एक हाईवे पर बुधवार शाम 17 गाड़ियां जलकर खाक हो गईं। गुरुवार सुबह यहां शवों को निकालने का सिलसिला जारी रहा। अब तक 16 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। मौतों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।

इस भीषण हादसे से 15 मिनट पहले हाईवे पर एक छोटा एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से वहां जाम लग गया था। 15 मिनट बाद एक तेज रफ्तार ट्रक ने आकर वहां खड़ी गाड़ियों को टक्कर मार दी। ट्रक में केमिकल रखा हुआ था। टक्कर की वजह से आग लग गई और गाड़ियों तक फैल गई।

वेनेजुएला के रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के डिप्टी मिनिस्टर ने कहा- पहले हादसे में एक ट्रक और 3 गाड़ियों की टक्कर हुई थी। इसके बाद हाईवे पर जाम लग गया कई अन्य गाड़ियां सड़क पर खड़ी हो गईं। तभी दूसरा ट्रक आया और उसने गाड़ियों को टक्कर मार दी।

उन्होंने कहा- खराब मौसम की वजह से ड्राइवर जाम को नहीं देख पाया होगा। हालांकि, लोगों का कहना है कि हाईवे की सड़क ठीक नहीं है, उसे सही से मेंटेन नहीं किया जाता।

सड़क हादसे के बाद पुलिस ने कहा- ये एक मल्टी व्हीकल कॉलिजन था, जिसमें एक साथ कई वाहन आपस में टकरा गए। हादसा हाईवे पर हुआ। इसकी जानकारी मिलते ही इमरजेंसी सर्विसेज घटनास्थल पर पहुंच गईं। घायल लोगों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। 28 अक्टूबर 2023 को मिस्त्र में भी ऐसा हादसा हुआ था। मिस्त्र की राजधानी काहिरा से 132 किलोमीटर दूर बहेरा इलाके में हाईवे पर एक के बाद एक कई गाड़ियों की टक्कर हो गई। लोकल मीडिया के मुताबिक हादसे में 35 लोगों की मौत हुई। 63 लोग घायल हो गए।

प्राइमरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक एक कार से पेट्रोल लीक होने के कारण इन गाड़ियों की टक्कर हुई थी और फिर उन गाड़ियों में आग लग गई। एक पैसेंजर बस भी इस हादसे का शिकार हुई। हालांकि बस में कितने लोग सवार थे, इसकी जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। 5 फरवरी 2023 को चीन के हुनान प्रांत में खतरनाक सड़क हादसा हुआ था। हाइवे पर 10 मिनट के अंदर 50 वाहन आपस में टकरा गए। इससे कई गाड़ियों में आग लग गई। इस हादसे में 16 लोगों की मौत हो गई, जबकि 66 लोग घायल हुए। चीन में कोहरे से विजिबिलिटी घटने से 200 गाड़ियां टकराई थीं

28 दिसंबर 2022 को कोहरे की वजह से करीब 200 गाड़ियां टकरा गई थीं। चीनी मीडिया ष्ह्ष्ह्नह्नक्क के मुताबिक, झेंगझोऊ शहर के झेंग्क्सिन हुआंगे ब्रिज पर दोनों तरफ से आने-जाने वाली गाड़ियां एक-दूसरे से टकरा गईं। यहां कोहरा इतना था कि 200 मीटर की दूरी पर भी कुछ नहीं दिख रहा था। इस दौरान कई लोग घायल हुए थे।

चीन ने कहा- लद्दाख हमारा हिस्सा, भारत का उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाना गलत

बीजिंगस एजेंसी।
कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाने पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर चीन ने कहा है कि वो भारत के फैसले को स्वीकार नहीं करता है। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा- इस फैसले का बीजिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत-चीन बॉर्डर का पश्चिमी हिस्सा हमेशा से चीन का रहा है।

चीन ने आगे कहा- हमने कभी भी भारत के एकतरफा और अवैध तौर पर स्थापित केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को मान्यता नहीं दी है। भारत के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ये सच्चाई नहीं बदल सकती कि सीमा का पश्चिमी हिस्सा चीन का है।

इससे पहले मंगलवार को चीन माओ निंग ने कश्मीर मामले पर कहा था- भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से विवाद चला रहा है। इसे शांतिपूर्ण तरीके से यूएनएससी के प्रस्तावों के तहत सुलझाना जरूरी है। चीन ने कहा- दोनों पक्षों को बातचीत और चर्चा के जरिए मसले को सुलझाना चाहिए ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाई जा सके।

भारत सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया था। साथ ही राज्य को 2 हिस्सों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था। तब चीन ने कहा था कि जम्मू-कश्मीर पर भारत का फैसला चीन को स्वीकार नहीं है और वो लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने के खिलाफ है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, आर्टिकल 370 हटने के बाद चीन ने अपने सहयोगी पाकिस्तान की तरफ से औपचारिक रूप से आपातकालीन बैठक बुलाने के बाद यूएनएससी में इस मुद्दे पर बंद दरवाजे के पीछे चर्चा करने को कहा था। दरअसल, 11 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के मुद्दे पर सुनवाई करते हुए सरकार के फैसले को बरकरार रखा था। स्ष्ट ने कहा था कि आर्टिकल 370 अस्थायी था। जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। राष्ट्रपति को यहां के फैसले लेने का पूरा अधिकार है।

हमास नेता ने कहा, वह इजराइल के साथ गाजा युद्धविराम पर चर्चा को तैयार

गाजा, एजेंसी। हमास नेता इस्माइल हानियेह ने कहा है कि गाजा पर शासन करने वाला फिलिस्तीनी गुट गाजा में युद्धविराम के लिए इजरायल के साथ किसी भी व्यवस्था या पहल पर चर्चा को तैयार है।शिन्हुआसमाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार हमास के राजनीतिक ब्यूरो के प्रमुख हनीयेह ने बुधवार को हमास से संबद्ध अल-अक्सा टीवी पर प्रसारित एक टेलीविजन भाषण में कहा, हम किसी भी व्यवस्था या पहल पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं जो (इजरायली) आक्रामकता पर रोक लगाती हो।

हनियेह ने कहा कि हमास ने गाजा में तत्काल युद्धविराम की मांग करने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव का स्वागत किया और गाजा संघर्ष को समाप्त करने के लिए सऊदी अरब और संयुक्त अरब-इस्लामिक शिखर सम्मेलन द्वारा सौंपी गई मंत्रिस्तरीय समिति के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने हमास द्वारा युद्ध के बाद की किसी भी राजनीतिक व्यवस्था को अस्वीकार करने की पुष्टि की, इसमें हमास और अन्य फिलिस्तीनी गुटों को शामिल नहीं किया गया है, और गाजा पर इजरायली हमलों को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ाने का आग्रह किया। इससे पहले, इजरायली मीडिया ने कई हमास नेताओं के कतर से अज्ञात गंतव्यों के लिए प्रस्थान की सूचना दी थी, इसमें लेबनान, ईरान या अल्जीरिया जैसे देशों में संभावित स्थानांतरण की बात कही गई। रिपोर्टों के संबंध में हमास की ओर से कोई पुष्टि नहीं की गई है।

यूएन में बोला भारत- जी20 में अफ्रीकी संघ को शामिल किए जाने से संयुक्त राष्ट्र सुधारों की ले प्रेरणा

संयुक्त राष्ट्र, एजेंसी। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कम्बोज ने कहा कि अपनी अध्यक्षता में जी20 के स्थायी सदस्य के रूप में अफ्रीकी संघ को शामिल करने की भारत की पहल सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और इससे ''बहुत ज्यादा पुराने संयुक्त राष्ट्र को सुरक्षा परिषद को समकालीन बनाने के लिए प्रेरित होना चाहिए। कम्बोज ने बुधवार को सुरक्षा परिषद सुधारों पर अंतरसरकारी वार्ता में कहा कि भारत की पहल पर अफ्रीकी संघ इस साल सितंबर में नई दिल्ली में हुए शिखर सम्मेलन में त्न20 का स्थायी सदस्य बन गया। उन्होंने कहा कि त्न20 में अफ्रीकी संघ को शामिल करने से यह सुनिश्चित हुआ है कि ''वैश्विक शासन और निर्णय निर्धारण के प्रभावशाली संस्थान में 'ग्लोबल साउथ की महत्वपूर्ण आवाज जुड़े।

'ग्लोबल साउथ शब्द का इस्तेमाल आम तौर पर आर्थिक रूप से कम विकसित देशों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। भारतीय राजदूत ने कहा, ''सुधार की दिशा में इस महत्वपूर्ण कदम से संयुक्त राष्ट्र को सुरक्षा परिषद को भी समकालीन बनाने के लिए प्रेरित होना चाहिए। व्यापक प्रतिनिधित्व आखिरकार, प्रभावशीलता और विश्वसनीयता दोनों के लिए एक शर्त है। उन्होंने कहा कि यह भारत का दृढ़ विश्वास है कि त्न20 में अफ्रीका की पूर्ण भागीदारी से यह समूह सही मायने में अधिक प्रतिनिधित्व वाला और प्रासंगिक संस्थान बनेगा।

कम्बोज ने कहा कि सितंबर 2024 में होने वाला 'समिट ऑफ द फ्यूचर संयुक्त राष्ट्र चार्टर के प्रति ''हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करने और सुरक्षा परिषद समेत महासभा में सुधार पर केंद्रित चार्टर की समीक्षा का एक ''स्वर्णिम अवसर उपलब्ध कराता है। उन्होंने याद किया कि इस साल सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा के वार्षिक उच्च स्तरीय सत्र के दौरान 85 से अधिक वैश्विक नेताओं ने महासभा से व्यापक और सार्थक सुधारों की मांग की। गौरतलब है कि भारत सुरक्षा परिषद में सुधारों के लिए लंबे समय से किए जा रहे प्रयासों में अग्रणी रहा है।

इज़राइल ने बंधक वार्ता फिर से शुरू करने के लिए मोसाद प्रमुख की कतर यात्रा की रद्द

जेरूसलम, एजेंसी। इजरायली सरकार ने संभावित दूसरे बंधक रिहाई समझौते पर बातचीत फिर से शुरू करने के लिए मोसाद प्रमुख डेविड बार्निया की कतर की यात्रा रद्द कर दी है। एक सूत्र ने गुरुवार को यह जानकारी दी। सूत्र ने सीएनएन को बताया कि इज़राइल की विदेशी खुफिया सेवा के निदेशक दोहा की यात्रा नहीं करेंगे, जहां पहले गाजा में हमास आतंकवादियों द्वारा बंधक बनाए गए बंधकों की रिहाई पर बातचीत हुई थी। इज़राइल के चैनल 13 ने पहली बार बुधवार को रिपोर्ट दी कि प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व में देश की युद्ध कैबिनेट ने यात्रा रद्द कर दी है। इसमें कहा गया है कि वरिष्ठ इजरायली अधिकारी बातचीत फिर से शुरू करने के लिए कतर नहीं जाएंगे। गौरतलब है कि 7 अक्टूबर को इज़राइल पर हमास के हमले के दौरान लगभग 240 लोगों को बंधक बना लिया गया था। इज़रायली प्रधान मंत्री के कार्यालय का मानना है कि गाजा में अब भी 135 बंधक हैं, इनमें से 116 जीवित हैं। 24-30 नवंबर तक हुए मानवीय विराम के दौरान, 86 इजरायली और 24 विदेशी बंधकों को रिहा किया गया था। इस महीने की शुरुआत में दोहा में हो रही बंधक वार्ता टूटने के बाद से औपचारिक बातचीत फिर से शुरू नहीं हुई है। सीएनएन ने सूत्रों के हवाले से कहा कि लेकिन इजराइल, अमेरिका और कतर ने चर्चा शुरू करने के तरीकों पर चर्चा जारी रखी है।

स्वामी प्रकाशक एवं मुद्रक:- देवेन्द्र मालवीय द्वारा श्री सिंध्दी विनायक प्रिंटर्स 26 बी देशबंधु परिसर प्रेस काम्प्लेक्स झोन 1 एम पी नगर भोपाल म.प्र. से मुद्रित एवं 773 / 19 मेघदूत नगर इंदौर म.प्र. से प्रकाशित सम्पादक डॉ. देवेन्द्र मालवीय

कार्यालय पता:- 435 ऑर्बिट मॉल विजय नगर, इंदौर मध्यप्रदेश मो:- 98276-22204 सभी विवादों का न्यायिक क्षेत्र इंदौर रहेगा।

दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित समस्त सूचनाए, विचार, आलेख विभिन्न समाचार के स्त्रोत एवं संकलन लेखकों के व संकलनकर्ता के स्वंय जिनका संकलन विभिन्न एजेंसियों, के माध्यम से किया गया है, अतः समस्त प्रकार के प्रकाशन हेतु संपादक, प्रकाशक, मुद्रक का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सहमत होना अनिवार्य नही है।